● वर्ष-2

● अंक-191

रायपुर, रविवार
02 अप्रैल 2023

● पृष्ठ-6

● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmailÐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यालय में 2 अप्रैल रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 4 अप्रैल मंगलवार को प्रकाशित होगा।

दुनिया में भारतीय रुपये की बढ़ती साख

■ **मलेशिया भी व्यापार में करेगा स्वीकार, 35 देश पहले ही दे चुके हैं मंजूरी**

नई दिल्ली। भारत और मलेशिया के बीच हमेशा से ही घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। दोनों ही देशों के बीच समय-समय पर उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन भी होता है। ये दोनों ही राष्ट्र आसियान समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

व्यापार के मामले में भी दोनों देशों के बीच काफी अच्छा संबंध रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय से भारत मलेशिया के बीच व्यापार को लेकर एक अहम जानकारी दी है। यह जानकारी दोनों देशों के होने वाले व्यापार के मुद्रा से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार अब अन्य मुद्राओं के अलावा रुपये में हो सकता है।

बता दें कि भारत के साथ अबतक 35 देशों ने रुपयों में व्यापार करने में अपनी रूचि दिखा चुके हैं। इसमें रूस के अलावा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग सबसे अधिक है। अभी तक भारत अपने हर चीज के लिए डॉलर में भुकतान करता है। इसके लिए भारत की तरफ से हर साल अरबों डॉलर खर्च होता है। यदि भारत भी आयात की जाने वाली चीजों का भुकतान रुपय के माध्यम से किया जाए तो डॉलर की निर्भरता को कम किया जा सकता है।

चीन के मुद्दे पर अफवाह फैलायी जा रही-जयशंकर

राहुल गांधी को विदेश से मिल रहे समर्थन पर कहा, किसी राजनयिक ने नहीं उठाया यह मुद्‌दा

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर कुछ 'अधूरे काम' हैं और दोनों ओर की सेनाएं तथा राजनयिक मुद्दे का हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जयशंकर ने चीन के साथ एलएसी पर हालात की तुलना यूक्रेन संघर्ष से करने के राहुल गांधी के प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा, ''आज यूक्रेन में जो हो रहा है, अगर आप दोनों पक्षों को सुनें तो, एक पक्ष कहेगा कि वह नाटो के विस्तार और यूक्रेन की सरकार की प्रकृति से खतरा महसूस कर रहा है।'' उन्होंने कहा, ''पश्चिम कहेगा कि रूस की विस्तारवादी मंशा है। भारत और चीन के बीच क्या है? यहां कोई नाटो नहीं है, सत्ता की कोई प्रकृति नहीं है। मुझे कहीं से तुलना नजर नहीं आती है।''

जयशंकर ने चीन से संबंधित मुद्दे पर यह भी कहा कि ऐसी ''बेबुनियाद अफवाहें'' फैलायी जा रही हैं कि भारत के गश्ती इलाकों में 'बफर जोन' छोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलवान संघर्ष 2020 के बाद से सेना और कूटनीति के संयोग से कुछ प्रगति हुई है, लेकिन उन्होंने माना कि दोनों पक्ष ''सबकुछ सुलझाने में सक्षम'' नहीं हुए हैं। एलएसी पर वर्तमान स्थिति के संबंध में जयशंकर ने कहा, ''जो कुछ भी हुआ है वह परस्पर सहमति और बातचीत से हुआ है। लेकिन अभी भी काम अधूरे हैं।'' उन्होंने यह भी कहा कि चीन के साथ संबंध को समझने के लिए व्यक्ति को दोनों देशों के बीच की समस्या की प्रकृति को भी समझना होगा।

राहुल गांधी मुद्दे पर बयान

वहीं राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता मुद्दे पर उन्हें मिल रहे विदेश से समर्थन के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि किसी विदेशी राजनयिक ने लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने का मुद्दा नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को उसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसका उन्होंने खुद समर्थन किया था। जयशंकर ने कहा कि

लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने चार साल पहले एक समुदाय के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर अफसोस जताने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा, ''कानून तो कानून है, जब तक कोई यह ना मान ले कि कानून उसके लिए नहीं बना है।'' यह पूछने पर कि क्या किसी राजनयिक ने उनके समक्ष यह मुद्द उठाया है, जयशंकर ने 'ना' में जवाब दिया।

यह पूछने पर कि वह अपने समकक्षों के सामने इस मामले को कैसे स्पष्ट करेंगे, जयशंकर ने कहा, ''चार साल पहले राहुल गांधी ने सार्वजनिक सभा में एक समुदाय के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह सार्वजनिक रिकॉर्ड में है। उस समुदाय के एक सदस्य ने इस पर तकलीफ माना और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।'' विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के पास अफसोस जताकर इस मामले को खत्म करने का अवसर था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना चुना। जयशंकर ने कहा कि यह कानून सत्तारुढ़ दल सहित करीब 10-12 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर लागू हो चुका है।

जी-20 पर बयान

वहीं दूसरी तरफ जी-20 मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि भारत जी20 को वैश्विक समृद्धि और विकास के उसके असल मुद्दे पर वापस ले आया है, जबकि यह संगठन साल भर पहले तक यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा कर रहा था और उससे प्रभावित हो रहा था। जयशंकर ने कहा कि जी20 वास्तविकता में वैश्विक शांति और सुरक्षा पर चर्चा करने वाला मंच नहीं था तथा भारत चाहेगा कि यह (जी20) दुनिया के कुछ 200 देशों से जुड़े मुद्दों पर लौट आए। विदेश मंत्री ने कहा, ''मुझे लगता है कि हमारा योगदान जी20 को जी20 के वास्तविक लक्ष्य पर वापस लाना है। जी20 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा के लिए प्राथमिक मंच नहीं है।'' उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दे मायने रखते हैं, लेकिन खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, देशों के लिए हरित वित्तपोषण जैसे गंभीर मुद्दे भी हैं।

जयशंकर ने कहा, ''हमने जी20 को भविष्य के लिए अच्छा विषय दिया है... वैश्विक कौशल मैपिंग। दुनिया में कहां-कहां कौशल है और दुनिया में किन-किन जगहों पर उसकी मांग है। वे दो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र में हैं। ऐसे में हम उन्हें साथ कैसे लाएं? मुझे लगता है कि विचार के लिहाज से हमने जी20 को यह बेहद दिलचस्प मुद्दा दिया है।'' विदेश मंत्री ने कहा कि जी20 का वास्तविक लक्ष्य दुनिया की समृद्धि और विकास है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां राजधानी रायपुर के निवास कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अभियान 'छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023' कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान सर्वेक्षण दल को हरी झण्डी दिखाकर प्रदेश के जिलों के लिए रवाना किया और अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी।

राज्यों पर सीआरपीएफ के 44000 करोड़ बकाया

संसदीय स्थायी समिति की 242वीं रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली। जब कभी किसी राज्य में दंगा, चुनाव या अन्य कोई ऐसी गतिविधि होती है, जिसमें कानून व्यवस्था के बिगड़ने का अंदेशा बना रहता है, तो वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ की तैनाती की मांग की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी बिना कोई देरी किए सीएपीएफ को संबंधित राज्य के लिए रवाना कर देता है। हालांकि इस तरह के अधिकांश टॉस्क सीआरपीएफ द्वारा पूरे किए जाते हैं। अब राज्यों की ओर केंद्रीय सुरक्षा बलों के 49 हजार करोड़ रुपये फंस गए हैं। मतलब, इतनी राशि बकाया है। इसमें अकेले सीआरपीएफ के ही 44083.51 करोड़ रुपये हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दर्जनभर राज्यों से कई बार आग्रह किया है कि इस राशि का भुगतान किया जाए, लेकिन राज्यों ने इतनी बड़ी राशि लौटाने की बजाए, उसे माफ करने की बात कह दी। केंद्र सरकार अब इस बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए सख्त कदम उठा सकती है।

राज्यसभा में पेश हुई गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की 242वीं रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल, गृह मामलों

की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों की तरफ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 49912.37 करोड़ रुपये बकाया हैं। जिन राज्यों ने अभी तक अपना तय भुगतान नहीं किया है, उनमें गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नगालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। संसदीय समिति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा था कि इस बकाया राशि के भुगतान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। मंत्रालय का जवाब था कि इस संबंध में नियमित आग्रह किया जा रहा है। प्रत्येक तीन माह में इस तरह का आग्रह किया जाता है।

मासिक स्तर पर उठाया जाए यह मुद्दा

गृह मंत्रालय ने संसदीय समिति को सूचित किया कि इन राज्यों ने उक्त राशि को माफ करने के लिए प्रार्थना दी है। समिति ने मंत्रालय से कहा है कि इसे लेकर कठोरता से बात की जाए। उक्त राशि के भुगतान के लिए राज्यों के साथ प्रमुखता से इस विषय को उठाया जाए। इतना ही नहीं, समिति ने मासिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। भारत सरकार को भी इस विषय में गंभीरता से प्रयास करने चाहिए, ताकि समयबद्ध तरीके से 49912.37 करोड़ रुपये का भुगतान संभव हो सके। आंतरिक ड्यूटी में सीआरपीएफ की बेहतरीन भूमिका, इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार इस बल की सराहना कर चुके हैं।

प्रमुख समाचार

सांसदी जाने के बाद राहुल को झटका, अब इस मामले में दर्ज हुआ मानहानि का केस

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी सांसद ही चली गई है। मोदी सरनेम मामले पर दिए गए बयान में फंसने के बाद राहुल गांधी के मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। दरअसल, उनके एक और बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। यह केस उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में दर्ज कराई गई है। वकील अरुण भदौरिया ने कमल भदौरिया की ओर से यह शिकायत कराई है। कमल भदौरिया आरएसएस के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। इस मामले की सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी। अब सवाल है कि किस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी की अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना कौरव से की थी और उसे 21वीं सदी का कौरव बताया था। इसी मामले को लेकर अब राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

करीब 10 महीने सजा काटकर जेल से बाहर निकले नवजोत सिंह सिद्धू

चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट द्वारा

एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के एक साल से भी कम समय बाद शनिवार को पटियाला जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पिछले साल 19 मई को सजा सुनाई गई थी और एक दिन बाद 20 मई को उन्होंने पटियाला की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने सजा काट ली और शनिवार को अपनी अवधि पूरी कर ली और पटियाला सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आए सिद्धू ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि सत्य को दबाने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है। सिद्धू को सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष छूट नहीं दी गई थी, भले ही वह 26 जनवरी को रिहाई के योग्य थे। उनकी रिहाई 10 मई को होने वाले जालंधर लोकसभा उपचुनाव से कुछ हफ्ते पहले हुई है। एआईसीसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन से यह सीट खाली हुई थी।

हावड़ा हिंसा की जांच सीआईडी को सौंपी गई, राजभवन गंभीर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गुरुवार को हुई हिंसा के बाद से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी

भाजपा ने हिंसा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने घटना की जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) को सौंप दी है। शुक्रवार को भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने घटना की जांच एनआईए और सीबीआई से कराने की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी सुनली चौधरी कर करेंगे। इस बीच जानकारी मिली है कि राज्यपाल ने कहा, दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्तियों में आग लगाना, वह भी पवित्र रामनवमी के दिन, एक बहुत ही भड़काऊ कृत्य है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। बोस ने कहा कि राजभवन आम आदमी के जीवन, संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंख और कान खुले रखेगा।

एटी रामास्वामी ने थामा भाजपा का दामन, हाल में ही जेडीएस से दिया था इस्तीफा

बेंग्लुरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को

लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बनी हुई है। नेताओं का दलबदल भी जा रही है। इन सब के बीच वरिष्ठ जेडीएस नेता एटी रामास्वामी ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने हाल में ही जनता दल सेक्यूलर से इस्तीफा दिया था। अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद एटी रामास्वामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसे कर्नाटक चुनाव से पहले जनता दल सेक्यूलर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एटी रामास्वामी ने कहा कि मैं वास्तव में पार्टी (भाजपा) के काम करने के तरीके से प्रभावित हूं। मैं पैसे की ताकत का शिकार हूं क्योंकि मैं हमेशा अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बात करता था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। मैं सिर्फ लोगों की सेवा करने का अवसर चाहता हूं।

इस साल खूब सताएगी गर्मी इन इलाकों में सामान्य से ज्यादा रहेगा तापमान

नई दिल्ली। मौसम विभाग की माने तो इस साल गर्मी खूब सताएगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल अप्रैल से जून के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण के पठार इलाके में तापमान सामान्य ही रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल केंद्रीय, पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत में भी लू ज्यादा दिनों तक चलेगी। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में चलने वाली लू के दिनों और उसके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से गर्मी ज्यादा रहेगी। अप्रैल महीने में बारिश सामान्य रहेगी। वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश सामान्य से थोड़ी कम रहने का अनुमान है। बता दें कि तापमान को प्रभावित करने वाली मौसमी घटना अल नीनो की तीन साल बाद वापसी हो रही है। अल नीनो के असर से 2023 में तापमान में वृद्धि होने की आशंका है।

समीक्षा

मोहन भागवत ने विभाजन को गलत बताया, अखंड भारत की वकालत की

नीरज कुमार दुबे

आरएसएस को बाहर से नहीं समझा जा सकता। आरएसएस देश के लिए जो सोच रखता है वह उन लोगों को समझ नहीं आ सकती जो परिवारवाद आधारित दलों में काम कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अमृतपाल सिंह इसलिए खालिस्तान की मांग कर रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। गहलोत को बता दें कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ था और खालिस्तान की मांग 1940 से हो रही है। गहलोत को समझना होगा कि जीवन के अद्वितीय आध्यात्मिकता-केंद्रित दृष्टिकोण को विश्व स्तर पर हिंदू नाम से जाना जाता है, जिसके कारण यह राष्ट्र हिंदू है और इसका विशेषण सनातन है। खास बात यह है कि यह शब्द हमारे द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों द्वारा दिया गया था, जिन्होंने हिंदुस्तान को बाहर से देखा और हमें हिंदू के रूप में अलग करने के लिए हमारी इस विशिष्टता को हिंदू राष्ट्र नाम दिया। यहां सवाल यह भी है कि जो भारत में पैदा हुआ है वह हिंदू नहीं है तो कौन है? दरअसल हिंदू शब्द का धार्मिक अर्थ निकालना गलत है। हिंदू शब्द तो शुद्ध रूप से भौगोलिक है। जरा संघ और कांग्रेस के लोगों की सोच का अंतर भी देखिये। कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया और आरएसएस का कहना है कि अखंड भारत सत्य है और खंडित भारत दु:स्वप्न है। आरएसएस कहता है कि भारत का विभाजन गलती है और कांग्रेस के लोग नेहरू के उस निर्णय पर गर्व करते हैं जिसके तहत देश का विभाजन हुआ था।

बहरहाल, जहां तक मोहन भागवत के बयान की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आजादी के सात दशक से अधिक समय के बाद भी पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं और अब वे मानते हैं कि भारत का विभाजन

एक गलती थी। हम आपको बता दें कि मोहन भागवत किशोर क्रांतिकारी हेमू कालाणी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से सिंधी समाज के लोग शामिल हुए। भागवत ने कहा कि अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत से अलग होने के सात दशक बाद भी पाकिस्तान में दुख है, जबकि भारत में सुख है।

हम आपको यह भी बता दें कि अमर बलिदानी हेमू कालाणी की जयंती पर आयोजित समारोह में सिंधी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, ''हमको नया भारत बसाना है। भारत खंडित हो गया। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई। अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, संस्कृति से अलग हो गए। क्या वे सुख में हैं?'' उन्होंने आगे कहा, ''यहां (भारत में) सुख है और वहां (पाकिस्तान में) दुख है।'' भागवत ने कहा, ''जो सही है, वह टिकता है। जो गलत है, वह आता है और जाता है।'' भागवत ने कहा कि सिंधी समुदाय सब कुछ गंवाकर भी शरणार्थी नहीं बना, लेकिन उसने पुरुषार्थी बनकर दिखा दिया। शहीद हेमू के नाम के साथ सिंध का नाम जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सिंधी समुदाय का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन इसका उल्लेख कम होता है।

उन्होंने कहा कि सिंधी समुदाय ने भारत नहीं छोड़ा था, वे भारत से भारत में ही आए थे। उन्होंने कहा, ''हमने तो भारत बसा लिया, लेकिन वास्तव में राष्ट्र खंडित हो गया। आज भी उस विभाजन को कृत्रिम मानते हुए सिंध के साथ मन से लोग जुड़े हैं। सिंधु नदी के प्रदेश सिंध से भारत का जुड़ाव रहेगा।'' भागवत ने कहा, ''आज भी अखंड भारत को सत्य और खंडित भारत को दुस्वप्न माना जा सकता है। सिंधी समुदाय दोनों तरफ के भारत को जानता है। आदिकाल से सिंध की परंपराओं को अपनाया गया।

दूसरी ओर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने पंजाब में अमृतपाल सिंह जैसे अलगाववादियों के उदय के लिए केंद्र में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई जा रही 'हिंदू राष्ट्र' की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। गहलोत ने पंजाब में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह के उदय के लिए भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 'हिंदू राष्ट्र' की विचारधारा पर निशाना साधते हुए कहा, ''हमें देश की चिंता करनी चाहिए।'' गहलोत ने कहा, ''देश हित में यही है कि अगर आप सब धर्म व जाति के लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो यह देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। एक नया आदमी आ गया अमृतपाल सिंह जो कह रहा है कि अगर मोहन भागवत व नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं। उसकी ऐसी हिम्मत क्यों हुई है।

यह हिम्मत इसलिए हुई है क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं।'' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, ''आाप सोचिएगा इस बात को। धर्म के नाम पर लोगों को खुश करना आसान काम होता है। आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग को बुझाने में वक्त लगता है। आप सोच सकते हैं तोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है।''

मूलभूत कार्यों को प्राथमिकता से करें क्रियान्वयन : ज्योत्सना महंत

दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिए निर्देश, सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न

कोरबा। लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक ली। उन्होंने योजनाओं की समीक्षा करते हुए गरीब और कमजोर लोगों के उत्थान के दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। सांसद ने जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल के कार्यों को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने कहा। सांसद ने पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की सूची की जानकारी विधानसभावार विधायकों को उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने समिति की बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिये गए निर्देशों को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने एक अप्रैल से प्रारंभ हो रहे बेरोजगारी भत्ता योजना और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की जानकारी देते हुए जनप्रतिनिधियों को इसमें सहभागिता की अपील की। उन्होंने बे-मौसम हो रही बारिश

व ओलावृष्टि से फसल नुकसान का तहसीलदारों के माध्यम से सर्वे कराने और आरबीसी-6-4 अंतर्गत मुआवजा प्रदान करने की बात कही।

दिशा समिति की बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने मनरेगा के कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्धारित गाइडलाइन अनुसार विभिन्न कार्य कराने कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी लेते हुए हितग्राहियों की सूची विधायकों को देने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने कहा। सांसद ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी लेते हुए कोविड-19 नियंत्रण के लिए प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में दवाई, बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ कोविड रोकथाम के लिए प्रबंध की जा रही है। सांसद ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सक तथा मरीजों के उपचार के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था और गर्मी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मड़वारानी, चैतुरगढ़, मातिनदाई आदि में विद्युत व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नये और उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने कहा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, रूरबन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, जल जीवन मिशन आदि की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

विस अध्यक्ष चरणदास महंत ने मशाल पकड़ व काले कपड़े पहनकर किया विरोध प्रदर्शन

कोरबा। केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के तानाशाही व द्वेषपूर्ण

रवैये के विरोध में नवगठित जिला सक्ती में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष व विधायक डॉ. चरणदास महंत की उपस्थिति में बड़ी तादाद में उपस्थित कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन कर मशाल जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के निरंकुश कार्यशैली और गुजरात की एक अदालत द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के ऊपर दर्ज आपराधिक अवमानना मामले में दो साल के लिए सजा सुनाए जाने पर उच्च अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिए जाने के बावजूद भाजपा सरकार ने आनन-फानन राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करवाने के साथ ही सांसद निवास को भी खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। जब न्यायालय द्वारा अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है तो फिर ऐसी स्थिति में दो दिनों के भीतर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त किए जाने और अपमानजनक तरीके से तुरंत ही सांसद निवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया जाना अपने आप में केन्द्र सरकार की निरंकुश कार्यशैली को दर्शाता है। बड़ी तादाद में उपस्थित कांग्रेसियों ने हाथ में मशाल लेकर व काले कपड़े पहन कर विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस के रैली में मशाल जलाने के दौरान 6 कार्यकर्ता आग से झुलसे

जगदलपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार देर शाम पूरे प्रदेश में राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस भवन से लेकर शहीद अमर स्मारक तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा, जगदलपुर विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन और चित्रकोट के विधायक राजमन बेंजाम एवं महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में मशाल रैली निकाला जा रहा था, इसी बीच मशाल जलाने के दौरान इस मशाल रैली में शामिल एनएसयूआई के करीब 06 कार्यकर्ता आग से झुलस गए। जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बेहतर इलाज की पूरी कोशिश की जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत अस्पताल में कांग्रेसी नेताओं के साथ भाजपा के पूर्व जगदलपुर विधायक संतोष बाफना भी महारानी अस्पताल पंहुचकर घायलों का हाल जाना।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मशाल जलाने में स्प्रिट का उपयोग किया गया, जिससे आग तेजी तेजी से भभक जाने से वहां खड़े 06 कांग्रेस कार्यकर्ता इसकी चपेट आ गये, वहीं इस आग से दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे बुरी तरह से झुलस गए। अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शरीर भी आग के चपेट में आए, एक छात्र के हाथ में मामूली चोट आई है। घटना के तुरंत बाद सभी झुलसे कार्यकर्ताओं को शहर के महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

बस्तर में निकली शोभायात्रा ने इतिहास रच दिया: केदार

जगदलपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने श्रीरामनवमी शोभायात्रा के लिए विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बधाई के पात्र हैं, इसके साथ ही शोभायात्रा में शामिल सभी समाजों के

प्रतिनिधि, सभी आम जनमानस, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और मीडिया के बंधुगण आप सभी को बधाई व आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर रामनवमी के दिन पूरे छत्तीसगढ़ सहित बस्तर संभाग के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर एवं सुकमा सहित बस्तर संभाग के सभी जिले एवं गांव-गांव में निकली भगवान राम की शोभायात्रा ने इतिहास रच दिया है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि श्रीराम बस्तर के कण-कण में बसे हैं, भगवान श्रीराम के चरण दंडकारण्य जिस क्षेत्र में पड़े उन इलाकों के जंगलों को आज भी काटे नहीं जाते हैं। भगवान श्रीराम के आदर्श और पदचिन्हों का आदिवासी समुदाय अनुसरण करते है, भगवान श्रीराम आदिवासियों के श्रद्धा का केंद्र हैं। बस्तर में आज भी आदिवासी अपने नाम के आगे या पिछे का राम उपनाम लिखते हैं, वहीं एक दूसरे से भेट करने पर राम-राम का अभिवादन करते हैं। रामनवमी के अवसर पर शहर और गांव गांव से रैली के माध्यम से निकले सनातन धर्मावलंबियों ने ऐसी शोभायात्रा निकाली कि सड़कों पर भगवान श्रीराम के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जय श्रीराम के गगनभेदी नारों ने पूरे जगदलपुर सहित बस्तर संभाग को भगवामय कर दिया। बस्तर संभाग में श्रीरामनवमी की इस शोभायात्रा को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जायेगा।

गरीब परिवारों के लिए विवाह एक चुनौती सरकार ने इसे दूर किया : राजस्व मंत्री

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाः राजस्व मंत्री, सांसद ने नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद

कोरबा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज कोरबा के राजेन्द्र प्रसाद नगर फेस वन दशहरा मैदान और कटघोरा के कवंर समाज भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। योजना अंतर्गत दोनों स्थानों पर आज 125 वर-वधू के जोड़े दांपत्य सूत्र में बंधे और सुखमय जीवन का संकल्प लेकर एक नई जिंदगी की शुरूआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास, पंजीयन एवं स्टाम्प मंत्री जय सिंह अग्रवाल और सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत सहित अन्य अतिथियों ने सभी वर-वधुओं को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया।

राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि आज जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक रीति-रिवाज का पालन करते हुए सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब परिवार के लिये अपनी बेटी का विवाह करना बहुत चुनौती से भरा होता है, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ कर

गरीब परिवारों के चुनौती को दूर करने के साथ उन्हें कर्ज में बोझ में दबने से बचाया है। राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विगत साढ़े चार साल से जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर सभी वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। पात्र हितग्राही शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 25 हजार रुपए के स्थान पर 50 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है जिसका लाभ आने वाले समय में जरूरतमंद लोगों को मिलेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री गरीबों और महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं, इसलिए राज्य के किसान, मजदूर, गरीब परिवार सहित अन्य जरूरतमंद लोगों की शादी की चिंता को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित किया जा रहा है। जिसका लाभ सभी जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जब घर में लड़की पैदा होती थी तब चिंता के साथ कर्ज का बोझ लद जाता था। सामाजिक कुरीतियों और परम्परा के नाम पर खेत, घर, जमीन बिक जाती थीं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन कर एक सार्थक योजना प्रारंभ कर क्रियान्वियत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो बेटी आज बहू बनकर किसी के घर में जा रही है, उन्हें अपनी बेटी मानकर घर में सम्मान दें। कटघोरा में आयोजित कार्यक्रम में भी सांसद श्रीमती महंत, कटघोरा विधायक श्री पुरूषोत्तम कंवर, पाली-तानाखार विधायक श्री मोहित राम केरकेट्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिव कला कंवर, खाद्य आयोग के सदस्य श्री हरीश परसाई, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय, गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री प्रशांत मिश्रा, छग मदरसा बोर्ड के सदस्य डॉ शेख इश्तियाक आदि ने आशीर्वचन के साथ सभी जोड़ो को विवाह के बंधन में बंधने की बधाई व शुभकामनाएं दी।

दंतेवाड़ा में लाल जहर के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण हुए लामबंद

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मौजूद आर्सेल मित्तल निप्पन स्टील कंपनी के आयरन ओर से निकलने वाली लाल मिट्टी ग्रामीणों के लिए जान की दुश्मन बन गई है। इस लाल मिट्टी से ग्रामीणों के सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। आयरन ओर के उत्खनन से निकलने वाली लाल मिट्टी को गांव में डंप किया जा रहा है। इससे सैकड़ों ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई है। इससे परेशान होकर 20 से अधिक गांव के हजारों ग्रामीणों ने गुरुवार को सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस लाल मिट्टी को डंप करने से 20 गांव के सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। यही नहीं उनकी जान का खतरा बढ़ भी गया है। ऐसे में वो चाहते हैं कि इस लाल मिट्टी के डंप को गांव से हटाया जाए। इससे पहले भी इस कंपनी के जिम्मेदार लोगो ने यहां के ग्रामीणों के साथ वादाखिलाफी की है। लोग विकास की राह देखते देखते थक गए हैं। यहां लोग लाल मिट्टी की वजह से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि इस लाल मिट्टी से उन्हें छुटकारा मिले। कंपनी की ओर से सभी नियम कानूनों को ताक में रखकर आयरन ओर का उत्खनन किया जा रहा है और ग्रामीणों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए सैकड़ों प्रभावित ग्रामीणों ने आदिवासी महासभा और सीपीआई के नेतृत्व में दंतेवाड़ा शहर में गुरुवार को रैली निकाली और यहां के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। दंतेवाड़ा जिले के कुंदेली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील कंपनी के द्वारा आयरन ओर का उत्खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं खनन करके लाल मिट्टी को कुंदेली ग्राम पंचायत के अलग अलग गांवो में ही डंप किया जा रहा है। मना करने के बावजूद भी कंपनी मनमानी कर रही है। इस लाल मिट्टी से पहले ही बैलाडीला और किरन्दुल के आसपास के कई गांव के लोग प्रभावित हैं। इस लाल मिट्टी से ग्रामीणों के सांस में लाल जहर घोला जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले में राज्य सरकार भी ध्यान नही दे रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कांग्रेस पार्षद की धमकी से विपक्ष का सदन से वॉकआउट

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम का बजट आज पेश किया गया। महापौर सफीरा साहू ने जैसे ही बजट भाषण शुरु किया, विपक्ष ने हंगामा शुरु कर दिया। निगम के नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाया कि योजनाओं के नाम के आगे मंत्री कवासी लखमा और सांसद दीपक बैज के नाम क्यों लिखे गए हैं, जबकि शहर विकास के लिए उन्होंने अपनी निधि से कुछ भी खर्च नहीं किया है। शहर में जो भी काम हो रहा है, केंद्रीय योजनाओं के तहत हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम क्यों नहीं लिखा गया है..? इस मामले को लेकर सदन में करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। पक्ष का आरोप है कि विपक्षी पार्षदों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि उनकी ओर से मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए गए, उसके बावजूद कांग्रेस पार्षद विक्रम डांगी ने टेबल ठोकर विपक्ष को धमकी दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन में विपक्ष का अपमान किया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने वॉक आउट कर दिया। पार्षदों का कहना है कि, इस बार का बजट पिछले बार के बजट का कॉपी पेस्ट है।

3 अप्रैल को रेल विस्तार कार्य रोकेगी किसान सभा

कोरबा। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के लक्ष्मण प्रोजेक्ट के पास रेल विस्तार कार्य से प्रभावित होने वाले आदिवासी परिवारों के लिए बुनियादी मानवीय सुविधाएं और आम रास्ता उपलब्ध करने की मांग जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन से की है। किसान सभा ने चेतावनी दी है कि इस मांग पर 3 अप्रैल को गेवरा.भैसमाखार के ग्रामीण विस्तार कार्य को रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे। उल्लेखनीय है कि गेवरा-भैसमाखार के ग्रामीण पीढ़ियों से यहां निवासरत हैं। यह क्षेत्र शहरी क्षेत्र नगर निगम अंतर्गत आता है, इसके बावजूद अभी तक इनके घरों तक सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंचा है। किसान सभा के कोरबा जिला अध्यक्ष तथा सचिव ने बताया कि मनगांव के नजदीक लक्ष्मण प्रोजेक्ट के पास नए साइलो निर्माण के साथ रेल विस्तार का काम हो रहा है, लेकिन रेल लाईन पार करने के लिए आम रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। इससे यहां निवास करने वाले एवं खेती-किसानी करने वाले ग्रामीणों का बाहरी क्षेत्र से संपर्क टूट जाएगा।

बच्चा चोरी के शक में कचरा बीनने वाले को बांधकर पीटा

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भीड़ ने कचरा बीनने वाले एक युवक को बिजली के पोल से बांध दिया। इसके बाद उसे जमकर लात-घूंसों और थप्पड़ से पीटा। भीड़ तब तक मारती रही, जब तक युवक बेहोश नहीं हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। आरोप है कि बस्ती की ही एक बच्ची को युवक चोरी कर ले जा रहा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक अभी बेहोश है। उसकी हालत ठीक होने पर पूछताछ की जाएगी। मामला दीपका थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, शांति नगर निवासी महिला प्रीति झा ने बताया कि उसकी तीन साल की बेटी रानू शुक्रवार शाम को घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान युवक पहुंचा और उसे बोरी में भरने लगा। प्रीति ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ एकत्र हो गई और बच्चा चोरी की बात पर युवक को पकड़ लिया। भीड़ ने युवक को रेलवे क्रॉसिंग के पास धन्वंतरि मेडिकल स्टोर के बगल में रस्सी से बिजली के पोल से बांध दिया और उसकी पिटाई की।

पोल से टकराकर खड़े ट्रक में जा घुसी कार, 5 घायल

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकराकर खड़ी ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, 56 वर्षीय पुन्नी राम सूरजपुर जिले के तिवरता का रहने वाला है। वह अपने परिवार के साथ प्रेमनगर जा रहा था। कार में पुन्नी राम, 42 वर्षीय चंद्रकांत प्रजापति, 42 वर्षीय हीरा प्रजापति, 25 वर्षीय मोनिका प्रजापति और 17 वर्षीय रश्मि प्रजापति सवार थे। वे कोरबा जिले के बंजारी मड़ई के पास पहुंचे ही थे कि पुन्नी राम को झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। बिजली के खंभे से टकराकर कार सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार सभी लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को पोड़ी उपरोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बिलासपुर सिम्स रिफर कर दिया गया है।

तेज रफ्तार पिकअप से टकराए बाइक सवार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार युवकों की बाइक तेज रफ्तार पिकअप से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि एक बाइक सवार दूर जा गिरा तो एक बाइक सवार का हाथ कंधे से अलग होकर सड़क पर जा गिरा। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना दो युवक आदि रजक (30) और संतोष रजक (30) अपने घर लौट रहे थे। दोनों गैराज में काम करते थे। आज दोपहर को अचानक बारिश होने के कारण दोनों जल्दी घर जाने के चक्कर में थे। इनका घर जिले के चिचगोहना गांव में था। हाइवे पर कक्का ढाबा के पास उनकी बाइक सामने से आ रही पिकअप से भिड़ गई। टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इनमें से एक युवक का हाथ कटकर बीच सड़क पर जा गिरा। वहीं दूसरा युवक सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरा। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

कोरबा निगम का पुनरीक्षित बजट सदन द्वारा अंगीकृत

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2022-23 एवं बजट वर्ष 2023-24 सदन द्वारा बहुमत के साथ अंगीकृत किया गया, वहीं सदन में प्रस्तुत अधिकांश प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने के साथ ही अन्य प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित किए गए, जबकि एक प्रस्ताव को सदन द्वारा स्थगित किए जाने व परीक्षण उपरांत सदन के समक्ष पुनः लाए जाने का निर्णय लिया गया, वहीं भूखण्ड व्ययन के संबंध में प्रस्तुत एक अन्य प्रस्ताव को सदन द्वारा निरस्त किया गया।

सभापति श्री श्यामसुंदर सोनी की अध्यक्षता तथा महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद व आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय की उपस्थिति में टी.पी.नगर स्थित राजीव गांधी आडिटोरियम में नगर पालिक निगम कोरबा का साधारण सम्मिलन आयोजित किया गया था, सम्मिलन में प्रस्तुत निगम का

पुनरीक्षित बजट वर्ष 2022-23 एवं बजट वर्ष 2023-24 बहुमत के आधार पर सदन द्वारा अंगीकृत किया गया। इसी प्रकार संत कबीर जयंती समारोह हेतु सहयोग राशि के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से, दादरखुर्द मानिकपुर में सार्वजनिक रथयात्रा के आयोजन में सहयोग के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। नगर पालिक निगम कोरबा के विभिन्न स्थलों में निर्मित दुकानों के आबंटन संबंधित प्रस्ताव आवश्यक संशोधन के साथ सर्वसम्मति से पारित हुआ। कोसबाडी के रिक्त भूखण्ड क्र. 69, 70, 72, 98/ए एवं 109 तथा नेहरूनगर कोरबा के भूखण्ड 94 एवं 95 के आबंटन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित हुआ। पं.रविशंकर शुक्लनगर विस्तार कोरबा स्थित रिक्त व्यवसायिक भूखण्ड क्र. सी./14 के व्ययन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित किया गया, जबकि पं.रविशंकर शुक्लनगर विस्तार कोरबा में आई.डी.एस.एम.टी. योजनांतर्गत रिक्त आवासीय भूखण्डों के आबंटन संबंधी प्रस्ताव को सदन द्वारा स्थगित किया गया तथा परीक्षण उपरांत पुनः लाए जाने का निर्णय लिया गया। शारदा विहार कोरबा के रिक्त भूखण्डों के आबंटन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित हुआ, वहीं मल्टीलेवल पार्किंग को व्यवसायिक काम्पलेक्स के रूप में परिवर्तित कर नगर पालिक निगम कोरबा को भवन का स्वामित्व हस्तांरित करने संबंधी प्रस्ताव भी बहुमत के आधार पर पारित हुआ। इसी प्रकार कोसाबाड़ी महाराणा प्रताप नगर कोरबा के रिक्त भूखण्डों के व्ययन संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पं.रविशंकर शुक्लनगर विस्तार कोरबा के रिक्त भूखण्डों के व्ययन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया। पुरानी बस्ती में बने नए भवन को सियान सदन के रूप में घोषित करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, वहीं केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 हेतु सहयोग प्रदान करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। 15वें वित्त योजना अंतर्गत तैयार किए गए सीवरलाईन कार्ययोजना के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सवारियों को उतारकर बस को लगा दी आग, फिर हुए फरार

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों में उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई के चलते बौखलाहट है जिसके चलते वह आए दिन कहीं ग्रामीण की हत्या कर रहे हैं, तो कहीं मशीनों को अलग-अलग स्थानों में आग लगा रहे थे। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह दंतेवाड़ा से नारायणपुर की ओर जा रही यात्री बस को नक्सलियों ने रोककर यात्रियों को बाहर निकाला। फिर बस में आग लगा दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। मामले की जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि नारायणपुर से दंतेवाड़ा आ रही यात्री बस को शनिवार की सुबह मालेवाही-बोदली के बीच आग के हवाले कर दिया गया।

ऐसी जानकारी थी कि इस सड़क निर्माण के बाद से ही नक्सलियों के विरोध के चलते लंबे समय

बाद आवाजाही शुरू की गई थी और यात्रियों को सुविधा मिल रही थी। किसी के हताहत होने की कोई अप्रिय घटना नहीं होने से राहत भी मिली है।

सुरक्षा बल के जवान घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। इस घटना में नक्सलियों ने किसी भी यात्री के साथ कोई बदसलूकी नहीं की है। वहीं आमजनों का कहना है कि नक्सलियों के द्वारा दिनदहाड़े बस को जला देने से यात्रियों के साथ ही ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सासाराम में बिगड़े माहौल को लेकर शाह का कार्यक्रम रद्द

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 2 अप्रैल को बिहार दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि, 2 अप्रैल को सासाराम में अमित शाह की एक रैली आयोजित थी जिसे अब स्थगित करना पड़ा है। सासाराम में हुए हिंसा के बाद भाजपा ने यह फैसला लिया है। इस बात की जानकारी भाजपा प्रवक्ता संजय मयूख ने दी। अमित शाह पटना और नवादा में अपना कार्यक्रम करेंगे। शनिवार शाम को अमित शाह बिहार पहुंच गए। सासाराम में अमित शाह सम्राट अशोक की जयंती समारोह में शिरकत करने वाले थे। इस दौरान वह एक जनसभा को भी संबोधित करते। हालांकि, अब इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अमित शाह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही पटना पहुंचेंगे।बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। दुर्भाग्य से हमें यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि हमारे लोगों पर बम चल रहे हैं।

अमित शाह की रैली रद्द होने पर नीतीश कुमार की दो टूक

पटना। बिहार में अमित शाह की रैली रद्द होने से राज्य की राजनीति गरमा गई है। जहां भाजपा राज्य सरकार पर लॉ एंड आर्डर न संभालने का आरोप लगाते हुए हमला कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ-साफ कह दिया कि बिहार में आने वाले हर मंत्री और नेता को पूरी सुरक्षा जिम्मेदारी के साथ से देते हैं। अमित शाह की रैली रद्द किसी और कारण से हुई होगी। हम लोग हर बात का ध्यान रखते हैं। वो अब नहीं आ रहे हैं तो कोई और बात होगी। हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, वे (भाजपा) लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दुख की बात है। हमें कल जैसे ही पता चला अलर्ट होकर तेजी से काम किया गया। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये किसी ने जानबूझकर किया है, हमने कहा है कि इस बारे में पता लगाया जाए। बता दें कि सासाराम और नालंदा में स्थिति को काबू करने के लिए इलाके में धारा 144 लगा दिया गया है।

राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली मारने की धमकी

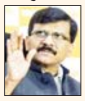

मुंबई। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेता संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोनई गिरोह ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस के मुताबिक संजय राउत को एक धमकीभरा पत्र मिला है जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी हत्या कर दी जाएगी। राउत ने इसकी पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने कहा, राउत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक धमकी भरा संदेश मिला जिसमें उनकी हत्या करने का जिक्र है। पुलिस जांच कर रही है। राउत ने धमकी के बाद सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार के आने के बाद हमारी सुरक्षा घटाई गई लेकिन हमने ज्यादा नहीं बोला है। राउत ने कहा, मुख्यमंत्री का बेटा एक गुंडे के साथ मुझ पर हमला करने की साजिश करता है इसको लेकर मैं पत्र लिखता हूं तो कहा जाता है कि यह एक स्टंट है। बकौल शिवसेना नेता- अगर हम सच बोलने पर आ गए तो भूकंप आ जाएगा।

केजरीवाल ने फिर उठाए पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए हैं और उन पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना देश के लिए बहुत जरूरी है। अपने बयान में केजरीवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का शिक्षित होना जरूरी है क्योंकि उन्हें एक ही दिन में कई बड़े फैसले लेने होते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ने पीएम मोदी के डिग्री पर संदेह को और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि अगर प्रधानमंत्री के पास डिग्री है और वह असली है तो दिखाई क्यों नहीं जाती है? उन्होंने यह भी कहा कि किसी का पढ़ा-लिखा या अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि पढ़ा लिखा आदमी नाली से गैस निकालने की बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में जानकारी लेना तो हर नागरिक का अधिकार है। कम पढ़ा-लिखा होना गुनाह नहीं है।

केजरीवाल को सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने दी चुनौती

गुवाहाटी। 2 अप्रैल को असम में अरविंद केजरीवाल की पहली राजनीतिक रैली से पहले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उनको चुनौती दी कि एक शब्द उनके खिलाफ यहां बोलकर दिखाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान के साथ 2 अप्रैल को असम जाएंगे। कथित तौर पर, केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि सरमा के खिलाफ अन्य राज्यों में मामले हैं। केजरीवाल के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने उनको चुनौती दी कि वे 2 अप्रैल को यहां आएं और उनके खिलाफ एक शब्द बोलकर दिखाएं। हिमंत ने कहा कि केजरीवाल उनके खिलाफ ये बोलकर दिखाएं कि हिमंत बिस्वा सरमा भ्रष्ट हैं। अगले दिन ही मैं मानहानि का मुकदमा दायर कर दूंगा। वही मैंने सिसोदिया के खिलाफ भी किया है। हिमंत ने कहा कि केजरीवाल ने विधानसभा में एक कायर की तरह यह बात बोली है। जहां मैं डिफेंड नहीं कर सकता था।

रानी कमलापति-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

नई सोच के तहत आगे बढ़ रहा देश : मोदी

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश दौरे पर थे। उन्होंने भोपाल में रानी कमलापति-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य उपस्थित रहे। अपने संबोधन की शुरूआत प्रधानमंत्री ने इंदौर हादसे पर दुख जताते हुए किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले इंदौर मंदिर में रामनवमी को जो हादसा हुआ, मैं उसके प्रति अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। इससे मध्य प्रदेश से दिल्ली का सफर और आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर किसी प्रधानमंत्री का इतने कम समय के अंतराल में दोबारा आना हुआ होगा। मोदी ने कहा कि आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं बन रही हैं। इस ट्रेन में यात्री के रूप में जो बच्चे जा रहे थे उन्होंने इस ट्रेन में सफर करने की अपनी उत्सुकता ज़ाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नई सोच, नई तकनीक की बात करता है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही व्यस्त रही। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे और हम देश वासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है।

प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत अब 21वीं सदी में नई सोच के तहत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही हैं, नई परंपराएं बन रही हैं, आज के कार्यक्रम इसी का एक उत्तम उदाहरण है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमारे राष्ट्र के कौशल, क्षमता और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि आज एक अप्रैल के इस कार्यक्रम पर हमारे कांग्रेस के मित्र यह बयान ज़रूर देंगे कि ये मोदी तो 'अप्रैल फूल' बना रहा है। लेकिन आप देखिए...एक अप्रैल को ही यह ट्रेन चल पड़ी है।

सभी सशस्त्र समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने और देश के विकास में अपना योगदान दे : अमित शाह

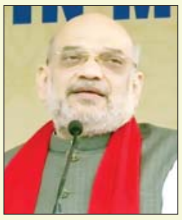

आइजोल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को मिजोरम के आइजोल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2,415 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। शाह ने दावा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम-डिवाइन परियोजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट में 276 फीसदी की बढ़ोतरी की है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के सभी आठ राज्यों की राजधानियों को 2025 से पहले रेल और सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा, एक समय यहां हिंसा होती थी, लेकिन आज जोरामथांगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, यह भारत में लोकतंत्र की सफलता की मिसाल है। आज यहां शांति है। शाह ने कहा, मैं पूर्वोत्तर के सभी सशस्त्र समूहों से अपील करता हूं कि वे मुख्यधारा में शामिल हों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनें और क्षेत्र व देश के विकास में अपना योगदान दें। मिजोरम पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। आज पूरा पूर्वोत्तर शांति, स्थिरता और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, एक जमाने में पूर्वोत्तर में उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा थी। रेल, सड़क और हवाई संपर्क की कमी थी और विकास का नामोंनिशान नहीं था। बीते नौ साल में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर की जनता के सहयोग से हम यहां शांति ला पाए हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है और भारत के अन्य हिस्सों के बराबर विकास पूर्वोत्तर में करने में हमें सफलता मिली है। भारत सरकार समग्र पूर्वोत्तर को विवादमुक्त, उग्रवाद मुक्त और शांति से युक्त बनाने का प्रयास कर रही है।

गृहमंत्री शाह ने कहा, 2014 की तुलना में 2021 में हिंसक घटनाओं में 67 फीसदी कमी आई है और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 60 फीसदी कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु में 83 फीसदी की कमी आई है। 2014 से अबतक लगभग आठ हजार उग्रवादी संगठन आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में आ चुके हैं।

उन्होंने कहा, हमने 2019 में एनएलएफटी के साथ शांति समझौता किया। 2021 में बोडो के साथ समझौता कर असम में शांति की स्थापना की। 2022 में कार्बी आंगलोंग समझौता करके हमने असम के ऊपरी हिस्से में शांति की स्थापना की। अफस्पा की परिधि में नौ साल में लगभग 70 फीसदी की कमी आई है। हमारे प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के विकास के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 53 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। 53 बार आने वाले वह पहले प्रधानमंत्री हैं।

शाह ने कहा, भारत सरकार के अलग-अलग मंत्री 725 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं और पीएम डिवाइन के साथ पूर्वोत्तर के बजट में 276 फीसदी की बढोतरी की है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्री 725 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं और पीएम डिवाइन के साथ पूर्वोत्तर के बजट में 276 फीसदी की बढोतरी की है और 2025 तक हम 1 लाख 25 हजार करोड़ की लागत से आठों राज्यों की राजधानी को सड़क, रेलवे और हवाई मार्गों से जोड़ने का काम पूरा करेंगे।

लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस चला रही अभियान

देश में एक दलीय शासन चाहती है भाजपा : गहलोत

जयपुर। मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। इसको लेकर देश की राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म है। कांग्रेस भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं, भाजपा की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। इन सबके में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा देश में एक दलीय शासन चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार जमीन पर लड़ाई लड़ रही हैं। अपने बयान में गहलोत कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस देश में जागरूकता अभियान चला रही है। वे (भाजपा) देश में एक दलीय शासन चाहते हैं। उन्होंने पंजाब की स्थिति पर चिंता जाहिक की और कहा कि पंजाब सरकार और भारत सरकार को जल्द ही (खालिस्तान मुद्दे का) हल निकालना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की भलाई के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। राजस्थान में डॉक्टरों के बवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला देश का पहला राज्य है। इसने लोगों में विश्वास पैदा किया है क्योंकि यह सुलभ और मुफ्त चिकित्सा उपचार का आश्वासन देता है। उन्होंने दावा किया कि इस पर आरएसएस समर्थित लॉबी राज्य के डॉक्टरों को गुमराह कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, सासाराम, बिहार और कुछ अन्य स्थानों पर रामनवमी के दिन हिंसा हुई। क्या यह अच्छी चीज है? ऐसे में देश में विकास कैसे हो सकता है? इससे रहले गहलोत ने कहा कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। अमृतपाल सिंह कह रहे हैं कि अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों न करूं? आग लगाना आसान है, लेकिन बुझने में समय लगता है।

कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थानों के बारे में संदेह पैदा कर रहे : भूपेंद्र

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कांग्रेस का विरोध करते हुए कहा कि वे सभी लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रकियाओं के बार में लोगों में संदेह पैदा करते हैं। कांग्रेस एक नापाक परियोजना में शामिल है। कांग्रेस ने वन संशोधन विधेयक 2023 को एक समिति को देने के फैसले का विरोध किया था। पर्यावरण मंत्री ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस शासन में भी बिलों को संयुक्त समितियों के पास भेजा गया था। यादव ने ट्वीट कर कहा कि जयराम रमेश का कहना है कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजना प्रक्रियाओं का अवमूल्यन और अपमान है। यादव का कहना है कि वह देखना चाहते हैं कि कांग्रेस द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पेश विधेयकों को संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सभी लोकतांत्रिक संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। वे अपनी नापाक परियोजना के तहत भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी नाम खराब कर रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

कोलकाता के खिलाफ पंजाब किंग्स ने जीता मुकाबला

नई दिल्ली। आईपीएल 2023 के दूसरे मुकाबले में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स था। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के समक्ष 191 रन बनाए थे। कोलकाता को जीतने के लिए 192 रन बनाने थे। लेकिन बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में कोलकाता की टीम 7 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। बारिश की वजह से जब एक खेल रुका, उस वक्त कोलकाता की टीम 7 विकेट पर 16 ओवर में 146 रन बना सकी थी। ऐसे में मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के तहत हुआ। इस नियम के तहत पंजाब किंग्स में आज के मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया।

देव ने चौथी वरीयता प्राप्त शशिकुमार को हराकर एकल सेफा में प्रवेश किया

नई दिल्ली. भारत के एस डी प्रज्जवल देव ने शुक्रवार को यहां हमवतन मुकुंद शशिकुमार को 1-6, 7-5, 7-6 (4) से हराकर आईटीएफ मैसुरु ओपन के एकल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। स्थानीय खिलाड़ी प्रज्जवल की विश्व रैंकिंग 1027 हैं और उन्होंने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए चौथी वरीयता प्राप्त मुकुंद को हराकर बड़ा उलटफेर किया।

मुकुंद की विश्व रैंकिंग 401 है। मुकुंद ने पहले सेट को 6-1 से अपने नाम किया और ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से जीत जायेगे। लेकिन इसके बाद प्रज्जवल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और अगले दोनों सेट जीत कर मुकाबला अपने नाम किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

तीसरी तिमाही में सरकार की कुल देनदारी बढ़कर 150.95 लाख करोड़ रुपये

नईदिल्ली। हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (सितंबर-दिसंबर, 2022) में सरकार की कुल देनदारी 2.6 फीसदी बढ़कर 150.95 लाख करोड़ रुपये हो गई। नवीनतम सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। सितंबर तिमाही में सरकार की कुल देनदारी 147.19 लाख करोड़ रुपये थी। इस तरह तिमाही आधार पर तीसरी तिमाही में सरकार की देनदारी 2.6 फीसदी बढ़ गई। वास्तविक संदर्भ में, सरकार के 'सार्वजनिक खाते' के तहत देनदारियों समेत उसकी कुल देनदारियां दिसंबर 2022 के अंत में बढ़कर 1,50,95,970.8 करोड़ रुपये हो गईं। वहीं 30 सितंबर तक कुल देनदारियां 1,47,572.2 करोड़ रुपये थीं। शनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर तिमाही में कुल निर्गम देनदारियों में से 89 फीसदी सार्वजनिक कर्ज के मद में रहा।

रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा भारत का रक्षा निर्यात

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो अब तक सर्वाधिक है। उन्होंने इस वृद्धि को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में देश का रक्षा निर्यात 12,814 करोड़ रुपये था। सिंह ने ट्विटर पर कहा, 'भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपये के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। यह देश के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है।' उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व में हमारा रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ता रहेगा।' केंद्र सरकार ने 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा हार्डवेयर के उत्पादन के साथ ही रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

अमेरिका चिप एक्ट से भारत को नुकसान का डर

नईदिल्ली। भारत ने अमेरिका के 280 अरब डॉलर के 'चिप फॉर अमेरिका' कार्यक्रम पर आपत्ति उठाई है। भारत का दावा है कि इससे विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन होता है और इससे विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को नुकसान होगा। अमेरिका की व्यापार नीति समीक्षा के दौरान हाल में नई दिल्ली ने यह सवाल उठाया और अमेरिका से चिप एक्ट को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। भारत ने कहा, 'यह (चिप एक्ट) वैश्विक प्रतिस्पर्धी विनिर्माताओं को लाभ की स्थिति से बाहर कर देगा। प्रस्तावित कदम उठाए जाने से खासकर विकासशील दुनिया के लोगों को इस क्षेत्र में एक समान काम करने की स्थिति नहीं रह जाएगी।' इसे लेकर चीन ने भी आपत्ति जताई है। बीजिंग ने कहा, अमेरिका लगातार कई साल से विभिन्न मौकों पर अन्य सदस्यों की सब्सिडी नीतियों की आलोचना करता रहा है। यह साफ किया जाना चाहिए कि क्या अमेरिका का लंबे समय से चल रहा यह रुख बदल गया है।'

भारतीय रुपये में मलेशिया भी करेगा व्यापार

नई दिल्ली। भारत और मलेशिया के बीच हमेशा से ही घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। व्यापार के मामले में भी दोनों देशों के बीच काफी अच्छा संबंध रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय से भारत मलेशिया के बीच व्यापार को लेकर एक अहम जानकारी दी है। यह जानकारी दोनों देशों के होने वाले व्यापार के मुद्रा से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार अब अन्य मुद्राओं के अलावा रुपये में हो सकता है। बता दें कि भारत के साथ अबतक 35 देशों ने रुपयों में व्यापार करने में अपनी रूचि दिखा चुके हैं। इसमें रूस के अलावा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग सबसे अधिक है। अभी तक भारत अपने हर चीज के लिए डॉलर में भुगतान करता है। इसके लिए भारत की तरफ से हर साल अरबों डॉलर खर्च होता है।

लालच की वजह से बढ़ा वित्तीय क्षेत्र में जोखिम

जैमिनी भगवती

गत 27 मार्च को फर्स्ट सिटिजन बैंक (एफसीबी) ने सिलिकन वैली बैंक (एसवीबी) का अधिग्रहण कर लिया। उसे अमेरिकी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) से उल्लेखनीय वित्तीय सहायता हासिल थी। मेरे कॉलेज के दिनों के एक मित्र ने पूछा कि एसवीबी का पतन क्यों हुआ। उसके सवाल में निहित प्रश्न यह था कि क्या 2008-09 में उत्तर अटलांटिक वित्तीय संघर्ष के बाद अमेरिका में अतिरिक्त नियामकीय नियंत्रण अपनाने से क्या ऐसी नाकामी को रोकने में मदद मिलती?

इसका एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण तो यह है कि बीते कई वर्षों के दौरान अमेरिका में नियामकीय मामलों में खतरे के निशान धुंधले पड़े हैं। उदाहरण के लिए जुलाई 2010 का डॉड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट सुधार और उपभोक्ता संरक्षण कानून को मई 2018 में इकनॉमिक ग्रोथ, रेग्युलेटरी रिलीफ ऐंड कज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट पारित करके काफी नरम कर दिया गया। बहरहाल, एसवीबी का पतन लीमन ब्रदर्स की तरह नहीं हुआ। बल्कि एसवीबी के पास लंबी परिपक्वता सीमा वाले बॉन्ड का भारी भरकम भंडार और अल्पावधि की उधारी वाले लोन पोर्टफोलियो थे।

एसवीबी की व्यक्तिगत जमा में करीब 90 फीसदी एफडीआईसी की 2,50,000 डॉलर की बीमा सीमा से अधिक के थे। संक्षेप में कहें तो एसवीबी तथा अमेरिका के अन्य मझोले बैंकों ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। इससे उनकी देनदारियों और परिसंपत्तियों के बीच परिपक्वता का भारी अंतर उत्पन्न हो गया था। हाल के वर्षों में क्रेडिट सुइस को बार-बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह निवेश बैंकिंग

में परिसंपत्ति प्रबंधन के अपने मूल काम से दूर हो गया था। अंत में 19 मार्च, 2023 को स्विस सरकार के जोर देने पर यूबीएस ने 3.2 अरब डॉलर की राशि खर्च करके क्रेडिट सुइस को खरीद लिया। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक स्विस सरकार यूबीएस को 9 डॉलर की राशि देने पर सहमत हो गई है। क्रेडिट सुइस के पतन की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंगलैंड और जी7 देशों के अन्य केंद्रीय बैंकों ने अपने प्रयासों को समन्वित किया ताकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। एक सवाल यह भी है कि क्या भारत के निजी या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रबंधकों को इसका अनुसरण करना चाहिए? गड़बड़ियों की घटनाएं, उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई), येस और आईसीआईसीआई बैंकों के प्रमुखों द्वारा की गई गड़बड़ियां व्यक्तिगत लालच का परिणाम थीं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की स्थापना सरकारी की बहुलांश हिस्सेदारी वाले संस्थानों मसलन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सरकारी बैंकों की फंडिंग की मदद से की गई थी। यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) और एनएसई ने धीरे-धीरे निजी क्षेत्र का दर्जा हासिल कर लिया और उनके शीर्ष प्रबंधन को सालाना 5 से 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाने लगा। अधिक बड़े और व्यवस्थागत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थान मसलन भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी के प्रमुखों को यूटीआई एएमसी और एनएसई के प्रमुखों की तुलना में बहुत कम भुगतान किया जाता है।

यह तथ्य है कि भारत के सरकारी बैंकों को कई अवसरों पर करदाताओं का धन दिया गया वहीं इन बैंकों का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे कर्जदार अनिवार्य तौर पर बड़ी निजी कंपनियां थीं। आमतौर पर उन पर व्यवस्थित जोखिम के प्राथमिक स्रोत के रूप में अंगुली नहीं उठाई गई। दुर्भाग्यवश ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता भी निजी क्षेत्र के कर्जदारों तथा कम क्षमतावान न्यायाधीशों के कारण धीरे-धीरे कम धारदार होती जा रही है। धीरे-धीरे यह मान्यता गहरी हो गई कि निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध वित्तीय संस्थानों में लालच से संचालित गलतियां होने की संभावना कम होती है क्योंकि शेयर बाजारों का अनुशासन अतिरिक्त जोखिम लेने पर लगाम लगाएगा।

राम नाम पर टिकी भविष्य की राजनीति

सिद्धार्थ शंकर गौतम

अगली बार की रामनवमी विशेष होगी क्योंकि अयोध्या में अस्थायी टेंट में बिराजे प्रभु श्रीराम, लक्ष्मणजी और जानकी माता के साथ नए बन रहे राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो चुके होंगे। तमाम राजनीतिक दल भी यह समझ चुके हैं कि राम के नाम पर भाजपा हमेशा से ही अग्रणी रही है और चूंकि राम का नाम जनमानस में आदर्श के रूप में स्थापित है अतः उन्होंने इस बार राम के चरित्र को स्वीकार करते हुए राम मंदिर पर चुप्पी साध ली है किंतु हाल ही में विपक्ष के पास राम नाम से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिसने भाजपा की पेशानी पर भी बल ला दिया है। दरअसल, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर विवाद है और उन्हें दलित व स्त्री विरोधी सिद्ध किया जा रहा है। रामचरितमानस की चौपाई पर समाजवादी पार्टी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक मुखर हो चुके हैं और भाजपा के मजबूत हिंदू वोट बैंक में इसी बहाने सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के मधेपुरा से विधायक और महागठबंधन सरकार में आरजेडी के कोटे से बिहार के शिक्षा मंत्री डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और दलित तथा महिला विरोधी बताया तो राजनीति में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मूकता ने इस बात पर भी मुहर लगा दी कि अपनी जाति के वोटों की फसल काटते-काटते नीतीश बाबू भी दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने का स्वप्न देखने लगे हैं। बिहार से प्रारंभ हुई यह रामचरितमानस विरोधी विकृत राजनीति उत्तर प्रदेश तक पहुंची और सपा के स्वामीप्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के विरोध में जिस प्रकार मोर्चा खोलते हुए इसे दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी बताया उससे भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग पर भी संकट के बादल छा गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी स्वामीप्रसाद मौर्य के बयानों का न तो विरोध किया और न ही समर्थन किंतु विरोध करने वाली दो महिला नेत्रियों को पार्टी से बाहर करके उन्होंने यह संकेत तो दे ही दिया कि यदि बात पिछड़े और दलित वोटों को भाजपा से तोड़ने की बात है तो वे स्वामीप्रसाद मौर्य के साथ हैं। हालांकि अपने विवादास्पद बयानों के चलते स्वामीप्रसाद मौर्य पर कई एफआईआर दर्ज हुई हैं किंतु जातिगत वोटों के लिए वे अभी भी रामचरितमानस के विरोध पर डटे हैं। लोकसभा चुनाव होने में अभी एक वर्ष का समय है किन्तु इसकी राजनीतिक बिसात बिछना प्रारंभ हो चुकी है। यह तय है कि अगला आम चुनाव राम और काम बनाम जातिवाद पर होना तय है। हाल ही में राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर दिए गए विवादास्पद बयान ने भाजपा को यह अवसर दिया है कि वह कांग्रेस की ओबीसी विरोधी छवि को समुदाय तक ले जाकर उसे भुनाए ताकि राजनीतिक रूप से सक्षम यह वर्ग कांग्रेस से विमुख होकर भाजपा को लाभ दे। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इसी मुद्दे पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने और उसके बाद उनके सरकारी आवास का आवंटन रद्द होने से जनमानस में कहीं न कहीं राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति दिखाई दे रही है। वैसे भी आम भारतीय जनमानस पहले से दबे-कुचले किसी भी व्यक्ति को अधिक त्रास देने को स्वीकार नहीं कर पाता। राहुल गांधी का राजनीतिक उभार अब जनता तय करेगी। वैसे सही राजनीतिक बिसात तो उत्तर प्रदेश में बिछ रही है जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और जो दल इनमें से अधिकांश पर विजयी होगा, केंद्र में सरकार बनाने का उसका दावा उतना ही मजबूत होगा। यदि बिहार में आरजेडी और यूपी में सपा जैसे दल रामचरितमानस पर पिछड़े एवं दलित वर्ग का मन बदलने पर सफल होते हैं तो अब तक भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरा गरीब मतदाता उससे छिटक सकता है क्योंकि भाजपा किसी भी हालत में रामचरितमानस का विरोध नहीं कर सकती।

भाषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

ललित गर्ग

राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक ताने-बाने को ध्वस्त कर रहे जहरीले भाषणों की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। संकीर्णता एवं साम्प्रदायिकता का उन्माद एवं 'हेट स्पीच' के कारण न केवल विकास बाधित हो रहा है बल्कि देश की एकता एवं अखण्डता भी खण्ड-खण्ड होने के कगार पर पहुंच गयी है। अब तो ऐसा भी महसूस होने लगा है कि देश की दंड व्यवस्था के तहत जहां 'हेट स्पीच' को नये सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है वहीं इस समस्या से निपटने के लिए 'हेट स्पीच' को अलग अपराध की श्रेणी में रखने के लिए कानून में संशोधन का भी वक्त आ गया है? राजनेताओं एवं तथाकथित धर्मगुरुओं के नफरती, उन्मादी, द्वेषमूलक और भड़काऊ भाषणों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर कड़ी टिप्पणी की है। एक मामले पर दो दिनों तक चली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसे नफरती भाषणों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? हालांकि सर्वोच्च न्यायालय पहले भी अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए राजनेताओं और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों को सार्वजनिक मंचों से बोलते वक्त संयम बरतने की नसीहत दे चुका है, मगर इस प्रवृत्ति में कोई सुधार नजर नहीं आता।

कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि समाज एवं राष्ट्र में उन्माद, अराजकता एवं अशांति पैदा करने के लिए नफरती भाषण देने की विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एवं संप्रदायों के कतिपय स्वनामधन्य नेताओं में परस्पर होड़ लगी हुई। इस संबंध में धर्म संसदों में आपत्तिजनक भाषण, राजनीतिक सभाओं में घृणा एवं नफरती बोल एवं विभिन्न चैनलों पर बहस के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां के दौरान हेट स्पीच के मामलों ने गंभीर एवं जटिल स्थितियों को जन्म दिया है। इस तरह भारत की गौरवमय संस्कृति को धुंधलाना, 'वसुधैव कुटुम्बकम' एवं सर्वधर्म सद्भाव के मंत्रों को ध्वस्त करना, भारत की एकता और अखण्डता को बांटना अक्षम्य अपराध है। इसलिये इनदिनों देश के ताजा मामलों में सर्वोच्च न्यायालय

ने 'हेट स्पीच' एवं नफरती बयानों-भाषणों पर तल्ख टिप्पणी की है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि नेता जिस दिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल छोड़ देंगे, नफरती भाषण भी बंद हो जाएंगे। भारत के लोग दूसरे समुदायों के लोगों का अपमान न करने, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सद्भावना कायम करने का संकल्प क्यों नहीं लेते? अदालत ने जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके भाषणों को लोग दूर-दूर से सुनने आत थे। वैसी नजीर अब कोई नेता क्यों पेश नहीं करना चाहता। अदालत ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि लोग समुदाय विशेष को लेकर ही नफरती भाषणों के खिलाफ चुनिंदा तरीके से मुकदमें क्यों दर्ज कराते हैं। उनमें सभी समुदायों और पंथों के खिलाफ दिए गए नफरती भाषणों पर सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती।

सर्वोच्च न्यायालय लंबे समय से ऐसे भाषणों, बयानों और तकरीरों के खिलाफ सख्त रहा है। बात केवल मुस्लिम कट्टरता एवं नफरती बयानों की ही नहीं है, करीब दो महीना पहले महाराष्ट्र में आयोजित सकल हिंदू समाज की रैली को लेकर भी न्यायालय ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि वहां कोई नफरती भाषण न होने पाए। उस रैली की वीडियो रिकार्डिंग का भी आदेश दिया था। जब जगह-जगह धर्म संसद करके समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती और भड़काऊ भाषण दिए गए थे, तब भी अदालत ने सरकार को सख्त लहजे में इस पर काबू पाने को कहा था। मगर राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं और नेताओं को शायद ऐसी अदालती आदेशों-निर्देशों की कोई परवाह नहीं है। खुद सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का उल्लेख किया है कि टीवी चैनलों पर आए दिन राजनीतिक दलों के प्रवक्ता सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले वक्तव्य देते रहते हैं। राजनेताओं से किसी भी ऐसे आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती, जिससे सामाजिक ताने-बाने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मगर इस दौर की राजनीति का स्वरूप कुछ ऐसा बनता गया है कि दूसरे धर्मों, संप्रदायों, समुदायों के खिलाफ नफरती भाषण देकर अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा है। निश्चित ही यह विकृत एवं घृणित सोच वोट की राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है। जाहिर है, उसमें भाषा की मर्यादा एवं शालीनता का भी ध्यान नहीं रखा जाता। स्थिति की गंभीरता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि अब तो राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा धार्मिक नेता भी अपने प्रवचनों में उत्तेजना और कटुता पैदा करने वाले शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इस प्रवृत्ति पर अविलंब अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि इस समस्या को नासूर बनने से पहले ही इस पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सके। उम्मीद है कि विधि आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र की ठोस कार्यवाही नहीं करने के बावजूद अब देश की शीर्ष अदालत हेट स्पीच के मुद्दे को लेकर जागरूक होते हुए उचित दिशा-निर्देश दे रही है।

पूरे विश्व में आज जब हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, तो देश के भीतर और देश के बाहर बैठी 'भारत विरोधी शक्तियां' एकजुट होकर साम्प्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता के ताने-बाने को क्षत-विक्षित करना चाहती है। ऐसी शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती हैं। भारत के लोगों में सहन करने की अद्भुत शक्ति रही है, लेकिन विदेशी ताकतें एवं देश की विरोधी शक्तियां उन्माद एवं नफरत के बीज बौने के तरह-तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। सोचने की बात तो यह है कि साम्प्रदायिक भावनाओं एवं नफरती सोच को प्रश्रय देने वाले सम्प्रदाय एवं समुदाय खतरे से खाली नहीं हैं। उनका भविष्य कालिमापूर्ण है। तभी सर्वोच्च न्यायालय में इन मामलों की सुनवाई कर रही बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस जोसेफ ने संयम, सहिष्णुता एवं सौहार्द की उपयोगिता को व्यक्त करते हुए कहा, 'सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता का सही अर्थ किसी को बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि मतभेदों को स्वीकार करना है।' जरूरत है कि हमारे समाज में ऐसे मतभेदों को स्वीकारते हुए मनभेद को न पनपने दे।

निश्चित ही राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक स्वार्थों के चलते देश को जोड़ने की बजाय तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, जो अक्षम्य है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से स्पष्ट है कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकारों को संजीदगी दिखाने की जरूरत है। मगर विडंबना है कि ऐसे देश तोडक मामलों को रोकने की जरूरत नहीं समझी गई और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एवं धर्मगुरु विद्वेष पर भाषण देते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ताजा टिप्पणी को राजनीतिक दल एवं विभिन्न सम्प्रदायों के धर्मगुरु-धर्मनेता कितनी गंभीरता से लेंगे, यह कहना मुश्किल है। क्या भारत के लोग खुद ही संकल्प नहीं ले सकते कि वे दूसरे नागरिकों और समुदायों का अपमान नहीं करेंगे। आजादी के अमृत-काल में नफरत एवं उन्माद की आंधी को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न धर्मों के बीच एकता, सौहार्द और समन्वय का उद्घोष करना होगा। तभी समूचा भारत नफरती सोच एवं हेट स्पीच के अशोभनीय-परिवेश से मुक्त होगा। तभी विनाश-शक्ति की अपेक्षा जीवन-शक्ति अधिक प्रभावशाली साबित होगी।

प्रसंग — जहाँ दया तहँ धर्म है

मुहम्मद गजनी का पिता सुबुक्तगीं पहले अलप्तगीं बादशाह का गुलाम था। वह हमेशा अपने टट्टू पर सवार हो शिकार के लिये निकलता था। एक बार रास्ते में उसे एक हिरनी के साथ उसका बच्चा दिखायी दिया। उसने बच्चे को पकड़कर उसकी टाँगें रस्सी से बाँधी और उसे टट्टू पर रखकर वह घर की ओर लौटने लगा। अकस्मात् उसे ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से कोई दौड़े आ रहा है। उसने जब मुड़कर देखा, तो उसे हिरनी आती दिखायी दी, जिसकी आँखों में आँसू जमा हो गये थे। वह करुण नेत्रों से अपने बच्चे की ओर देखती चली आ रही है। यह दृश्य देख सुबुक्तगीं के हृदय में भी करुणा जाग्रत हो। उठी। उसने तुरन्त बच्चे को रस्सी से मुक्त कर दिया। बच्चे को मुक्त देख हिरनी फौरन उसके पास गयी, मगर उसकी आँखें अब भी सुबुक्तगीं पर गड़ी हुई थीं कि कहीं वह बच्चे को फिर से न छीन ले। सुबुक्तगीं ने उसकी आँखों का भाव पहचान लिया और वह वहाँ से चुपचाप चलता बना।

रात को सुबुक्तग को स्वप्न में पैगम्बर साहब के दर्शन हुए। उन्होंने उससे कहा तूने दया करके एक असहाय और मूक प्राणी को मुक्त किया है। इसे खुदा ने बहुत पसन्द किया है और उसने तेरा नाम बादशाहों की फेहरिस्त में लिखवा दिया है। वह तुझसे यहाँ उम्मीद करता है कि आगे भी तू यही बरताव अपनी रैयत के साथ भी करेगा।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1998 मिनेसोटा में विश्व पुरुष फिगर स्केटिंग चैंपियन आयोजित किया गया था।
2001 मेट्रोडोम मिनियापोलिस में 63 वें एनसीएए पुरुषों की बेसबॉल चैम्पियनशिप आयोजित की गई थी।
2006 मध्य अमेरिका में 60 से अधिक बवंडर छू गए, जिससे 27 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।
2007 सोलोमन द्वीप में शक्तिशाली सुनामी आयी।
2009 डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री आंद्रे फोग रासमुसेन को 1 नाटो शिखर सम्मेलन में नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।
2010 ब्राजील के भूमि सुधार कार्यकर्ता पेड्रा अलकंतरा डी सूजा को दो लोगों ने उनके सिर पर पांच बार गोली मारी, जबकि उन्होंने अपनी साइकिल सराय पारा की सवारी करने की कोशिश की।
2011 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोगों द्वारा प्रो और कार्बन विरोधी कर रैलियों में भाग लिया गया।
2012 1940 अमेरिकी जनगणना के डेटा को 132 मिलियन लोगों की जानकारी सहित जारी किया गया था।
2012 अमेरिका के कैलिफोर्निया के ओकलैंड में एक कोरियनक्रिस्टियन कॉलेज ओइकोस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बंदूकधारी ने लोगों पर गोली चला दी, जिससे सात लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए।
2013 बर्मा के यांगून शहर में एक मस्जिद के अंदर भीषण आग लगने से 13 बच्चों की जलकर मौत हो गई।
2013 एक शीर्ष वैज्ञानिक और नासा के प्रोफेसर, जेम्स हेन्सन, ग्लोबल वार्मिंग सक्रियता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेवानिवृत्त हुए।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगतत्त्वापनिषद् (भाग-03)

गतांक से आगे...

इसी तरह से ज्ञानेन्द्रियों के जितने भी विषय हैं, उन सबको योगी अपनी अन्तरात्मा में धारण करे तथा प्रतिदिन एक प्रहर तक इस (क्रिया) का आलस्य त्यागकर प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करे। इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जैसे-जैसे योगी की चित्त-शक्ति बढ़ती है, वैसे-वैसे ही उसको दूर- श्रवण, दूर-दर्शन, क्षण भर में सुदूर क्षेत्र से आ जाना, वाणी की सिद्धि, जब चाहे जैसा रूप ग्रहण कर लेना, अदृश्य हो जाना, उसके मल-मूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाना, आकाश मार्ग से गमन कर सकना आदि सिद्धियाँ प्रकट होने लगती हैं।

बुद्धिमान् श्रेष्ठ योगी सदैव योग की सिद्धि की ओर ही ध्यान बनाये रखे। परन्तु ये सभी सिद्धियाँ योग-सिद्धि के लिए विघ्नरूप हैं, बुद्धिमान् योगी साधक को इन (सिद्धियों) से बचना चाहिए। अपनी इस तरह की सामर्थ्य को कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ योगी को जन सामान्य के समक्ष अज्ञानी, मूर्ख एवं बधिर की भाँति बनकर रहना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को सभी तरह से छिपाकर गुप्त रीति से रहना चाहिए। शिष्य-समुदाय अपने-अपने कार्यों के लिए योगी साधक से निश्चित ही प्रार्थना करेंगे; किन्तु योगी को उन (शिष्यगणों) के काम में पड़कर अपने कर्त्तव्य (अभ्यास) को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। उस योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके सभी तरह के क्रिया-कलापों को छोड़कर योग के अभ्यास में लगा रहे। इस प्रकार लगातार योग के अभ्यास से उसे घटावस्था की प्राप्ति हो जाती है; परन्तु इस तरह की सिद्धि अभ्यास के द्वारा ही मिल सकती है, केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता।

अतः योगी को निरन्तर प्रयत्नपूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। तदनन्तर अभ्यास योग से परिचय अवस्था का शुभारम्भ होता है। उस (अवस्था) के लिए प्रयत्नपूर्वक वायु से प्रदीप्त कुण्डलिनी को साधना के द्वारा जाग्रत् करके भावनापूर्वक सुषुम्ना में अवरोध रहित प्रवेश कराना। तत्पश्चात् वायु के सहित चित्त को महापथ में अग्रसर करना चाहिए। जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, उसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश इन पञ्च महाभूत रूपी देवों की पाँच प्रकार की धारणा हो जाती है।

पैरों से जानु (घुटनों तक पृथ्वी तत्त्व का स्थान बतलाया गया है। चार कोनों से युक्त यह पृथ्वी, पीत वर्ण, ल कार से युक्त कही गयी है। पृथ्वी तत्त्व में वायु को आरोपित करते हुए ल कार को उसमें संयुक्त करके उस स्थान में स्वर्ण के समान रंग से युक्त चार भुजाओं एवं चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से पाँच घटी (2 घंटे) तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्त्व को जीत लेता है।

क्रमशः...

विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस

विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस दुनियाभर में प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अप्रैल के दिन को विश्व आत्मकेंद्रित (ऑटिज़्म) जागरूकता दिवस घोषित किया था। इस दिन उन बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के कदम उठाए जाते हैं, जो ऑटिज़्म ग्रस्त होते हैं और उन्हें सार्थक जीवन बिताने में सहायता दी जाती है। नीला रंग ऑटिज़्म का प्रतीक माना गया है। वर्ष 2013 में इस अवसर पर ऑटिज़्मग्रस्त एक व्यक्ति कृष्ण नारायणन द्वारा लिखित एक पुस्तक और अलग ही आशा शीर्षक एक गीत जारी की गई। भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार प्रति 110 में से एक बच्चा ऑटिज़्मग्रस्त होता है और हर 70 बालकों में से एक बालक इस बीमारी से प्रभावित होता है। इस बीमारी की चपेट में आने के बालिकाओं के मुकाबले बालकों की ज्यादा संभावना है।

क्या है ऑटिज़्म- ऑटिज़्म या आत्मविमोह / स्वलीनता, एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो विकास संबंधी एक गंभीर विकार है, जिसके लक्षण जन्म से या बाल्यावस्था (प्रथम तीन वर्षों में) में ही नज़र आने लगते है और व्यक्ति की सामाजिक कुशलता और संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है, साथ ही इसकी वजह से उनके न्यूरोसिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे प्रभावित व्यक्ति, सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है जैसे एक ही काम को बार-बार दोहराना। यह जीवनपर्यंत बना रहने वाला विकार है। ऑटिज़्मग्रस्त व्यक्ति संवेदनों के प्रति असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि उनके एक या अधिक संवेदन प्रभावित होते हैं। इन सब समस्याओं का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है, जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं से असामान्य तरीके से जुड़ना। ऑटिज़्म का विस्तृत दायरा है।

ऑटिज़्म के लक्षण- ऑटिज़्म के दौरान व्यक्ति को कई समस्याएं हो सकती हैं, यहां तक कि व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। ऑटिज़्म के रोगी को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। कई बार ऑटिज़्म से ग्रसित व्यक्ति को बोलने और सुनने में समस्याएं आती हैं। ऑटिज़्म जब गंभीर रूप से होता है तो इसे ऑटिस्टिक डिस्ऑर्डर के नाम से जाना जाता है लेकिन जब ऑटिज़्म के लक्षण कम प्रभावी होते हैं तो इसे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर (ृस्ष्ठ) के नाम से जाना जाता है। एएसडी के भीतर एस्पर्जर सिंड्रोम शामिल है।

ऑटिज़्म का प्रभाव-ऑटिज़्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 तक विश्व में तकरीबन 7 करोड़ लोग ऑटिज्म से प्रभावित थे।

गलती करके भी माफी नहीं मांगता नेहरु परिवार

श्याम जाजू

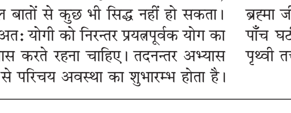

राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में बेबुनियाद बातें करना, गलत शब्दों को प्रयोग करना, अनावश्यक लांछन लगाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करना ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे अनेक प्रसंगो से ही उनकी सार्वजनिक व राजनीतिक छवि हास्यास्पद व मजाकिया के रूप में स्थापित हो गई है। इसका बड़ा नुकसान उनकी पार्टी को तो हुआ ही है पर साथ-साथ गांधी परिवार का स्वभाव चर्चा में आ जाता है। ऐसे ही अपने गलत बयान के कारण सूरत के विधायक पूर्णेष मोदी ने उनपर मानहानि का मुकदमा किया था और अभी-अभी उसका जजमेंट आकर उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई। अभिव्यक्ति स्वातंर्त्य, व्यक्ति स्वातंर्त्य इसका पर्याप्त फायदा उठाते हुए व्यक्ति द्वेष का अतिरेक करकर राहुल जी सार्वजनिक सभाओं में बोलते रहते हैं। मोदीद्वेष से ओतप्रोत होकर 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी जी की पिछड़ी जाति का अपमान करते हुए उन्होंने कहा था कि देश के सब चोरों का सरनेम मोदी क्यों है।

सोने का चम्मच मुंह में लेकर राजघराने में राहुल जी का जन्म हुआ। इसलिए वो एक अतिसामान्य गरीब परिवार से आये हुए और गये तीन दशक से अपने कतृत्व से समाज के मन को प्रभावित करने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत ही हीनभाव रखते हैं। सत्ता में रहने का अधिकार केवल एक ही परिवार को है, ऐसा भ्रम राहुल जी और कुछ कांग्रेसी मन में रखे हुए हैं। सत्ता वियोग के दुःख से हताश होकर राहुल जी के मन में हताशा, निराशा और समय-समय पर अहंकार भी व्यक्त होता है। गांधी परिवार की तीन पीढ़ियों से हम इसी मानसिकता से परिचित हैं। वो अपने गलत व्यवहार या बयानों पर कभी माफी नहीं मांगते। नेताजी सुभाषचंद्र बोस जब बहुमत से कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब राहुल जी के परनाना नेहरू जी परेशान थे। उनके द्वेषपूर्ण व्यवहार से ही नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को भारत के बाहर जाना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनकी मृत्यु का गूढ़ रहस्य कभी खुला नहीं। सुभाष बाबू के बारे में जो अन्याय कारक व्यवहार हुआ उसके बारे में नेहरूजी ने भी कभी माफी नहीं मांगी थी।

सावरकर व संघद्वेष यह गांधी परिवार की खानदानी परिपाटी है। इसी कारण राहुल जी के परनाना नेहरूजी ने गांधी हत्या के केस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वातंर्त्यवीर विनायक दामोदर सावरक जी पर आरोप लगाये। देशभक्त स्वयंसेवकों को और सावरकर जी को जेल में बंद किया, संघ पर पाबंदी लगाई, बदनाम करने की कोशिश की पर न्यायालय ने इन सभी को निर्दोष साबित किया, तब भी नेहरू जी ने माफी नहीं मांगी थी। पाकिस्तान के पहले युद्ध में नेहरू जी के कार्यकाल में कश्मीर का कुछ पार्ट जो आज भी पीओके के रूप में जाना जाता है वो चला गया। आज तक वो भू-भाग वापस नहीं आ पाया है। इसका जिक्र कहीं भी गांधी परिवार ने नहीं किया, माफी मांगना तो दूर की बात है। 1962 के युद्ध में नेहरूजी के चाइना प्रेम के कारण हिंदी चीनी भाई-भाई के नारों के बावजूद अपना कुछ भू-भाग चाइना के पास चला गया। बॉर्डर वाले क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत ना होने से अपने सैनिकों को युद्ध में बड़े पैमाने पर शहादत देनी पड़ी, देश को हार स्वीकारनी पड़ी, लेकिन नेहरूजी ने देश से माफी नहीं मांगी। राहुलजी की दादी इंदिराजी ने न्यायालय का अपमान करते हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, सेन्सरशिप जारी की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया, नागरिकों की जबरदस्ती नसबंदी की, सभी देशभक्तों के साथ-साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य कृपलानी जी, वाजपेयी जी इनको भी जेल में रखा। परिणामतः कांग्रेस चुनाव में पराजित हुई और वो सत्ता से बाहर हो गई। इतना होने के बावजूद राहुलजी की दादी इंदिराजी व चाचा संजय गांधी जी ने देश से माफी नहीं मांगी। 1984 के सिखों के नरसंहार के बाद राहुल जी के पिता स्व. राजीव जी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि बड़ा वृक्ष गिरने के बाद जमीन तो हिलती ही है। सिख समुदाय के लोगों की हत्याओं के विषय में उन्होंने कभी पश्चाताप व्यक्त नहीं किया, ना कभी माफी मांगी। गांधी परिवार के नस-नस में सरंजामी प्रवृति है, भारत उनको अपनी जागीर लगती है। नेता व कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा ना रख कर उनका अपमान करना ये उनके खून में है। इसकी ही परिपाटी में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश पत्रकार परिसर में सार्वजनिक मंच पर फाड़ते हैं। इतना ही नहीं गांधी परिवार ने अपने वरिष्ठ नेताओं स्व. निजलिंगप्पा, स्व. डॉ नीलम संजीव रेड्डी, स्व. सीताराम केसरी, स्व. मोरारजी देसाई, स्व. नरसिम्हा राव को भी अपमानित किया है। राहुल जी का बदसलूकी का व्यवहार केवल देश में, संसद में या सार्वजनिक सभाओं तक सीमित नहीं रहता है। विदेशों में भी देश की बदनामी करना व गलत लांछन लगाने का काम वो करते रहते हैं। देश, काल, परिस्थिति का कोई बंधन वहां काम नहीं करता। इतना होने के बावजूद वो संसद में माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगने की परिपाटी उनके परिवार में है ही नहीं। देशहित से ज्यादा उनका अपना अहंकार है। भारत की न्याय व्यवस्था में कानून सबके लिए समान काम करता है। इस कारण राहुल जी के बेबुनियाद बयान की सजा उनको न्यायालय ने सुनायी है। राहुल जी के अपरिपक्व व अहंकारी वक्तव्यों से बार-बार देश के सामाजिक सद्भाव का, देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों का अपमान हुआ है।

गांधी आज

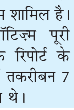

स्वावलंबी और व्यापारी खादी (भाग-01)

किसान अपने ही खेत की कपास से खुद ओट-धुन काल ले और सिय बुनाई के पैसे खर्च करे तो वह खादी मिल के कपड़े की अपेक्षा उसे सस्त पड़ती है। यह वस्त्र-स्वावलंबन कहलाता है। जो किसान इसके साथ हुई की क्रिया सीखाकर बुनने लगे तो वह तो पूरा स्वावलंबी हो जाएगा और कपड़ा उसे बहुत सस्ता पड़ेगा। किसान बाज़ार से खास करके राह खर्च लगाकर आई हुई-कई खरीदकर पूर्वोक्त क्रियाएं खुद करे तो वह कपड़ा मिल के कपड़े से आज कुछ महँगा पड़ता है, पर सूत के कस और अंक के सुधार होने से इसकी कसर निकल जाएगी। खादी को टिकाऊ बनाने में जितने अंश में सफलता प्राप्त होगी उतने अंश में खादी सस्ती हुई समझना चाहिए। व्यापारी खादी की किस्मों और सस्तापन में जो तरक्की अबतक हुई है उसके भाव के विषय में और साथ ही चरखे का काम सही दिशा में किया गया उद्योग है, इस बारे में भी कोई शंका नहीं रहती। परंतु व्यापारी खादी को सस्ती करने में जो मेहनत उठाई गई है वह सब सही रास्ते पर नहीं हुई है, यह अब साफ दिखाई दे रहा है। जिन गरीबों के हित के लिए यह कार्य उत्पन्न हुआ है उन्हें इसके द्वारा गुजर भर की मजदूरी मिलती है या नहीं. इस ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया। 5. खादी या दूसरे ग्राम-उद्योग के उद्धार के लिए काम करनेवाले सेवकों और संघों का धर्म केवल किसी उद्योग को जैसे तैसे चालू कर देना ही नहीं है, बल्कि इस बात की जाँच करना भी है कि उन उद्योगों में लगे हुए लोगों को रोटी चलने भर की मजदूरी मिलती है या नहीं। यदि परिश्रम करने को उतना पारिश्रमिक न मिलता हो तो कहना होगा कि उस उद्योग के से गरीब की मेहनत का बेजा फायदा उठाया जाता है। इसके सिवा उन्हें इतनी मजदूरी चुका दी या मिल गई, इतने से ही संतोष नहीं मान लेना चाहिए।

क्रमशः...

छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता शुरू

युवाओं ने कहा सपनों को मिलेगी उड़ान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल यानी की शनिवार से बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हुई है। योजना के पहले दिन सीएम भूपेश ने पंजीयन कराने वाले 4 बेरोजगार छात्र-छात्राओं को बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश पत्र दिया। इन चारों को ये नहीं पता था कि आवेदन के कुछ ही समय बाद इन्हें योजना का लाभ मिलने वाला है। इन चारों लोगों ने बेरोजगारी भत्ता पाने के बाद सरकार को धन्यवाद दिया है। आइए जानते हैं बेरोजगारी भत्ता पाने वाले छात्रों का क्या कहना है।

बेरोजगारी भत्ते से खरीदेंगी किताबें

रायपुर जिले की निवासी पूजा चंद्रवंशी बीएड की छात्रा हैं। पूजा गुढ़ियारी में रहती हैं और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पूजा का सपना शिक्षक बनने का है। इसलिए बीएड की पढ़ाई कर रहीं हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए जिन महंगे किताबों की जरुरत होती है वो अपने सहयोगियों से लेकर पढ़ती थी। बेरोजगारी भत्ता का आवेदन करने के बाद तुरंत उनका नाम सेलेक्ट हो गया। पूजा का कहना है कि, अब इस भत्ते से अपने लिए किताबें खरीद सकेंगी।

फिजिकल डाइट के लिए करुंगी इस्तेमाल

मुक्तेश्वरी रायपुर के मोवा में रहती हैं। मुक्तेश्वरी एथलीट हैं और फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहती हैं। मुकेश्वरी को अपनी रेगुलर डाइट और अपनी रूटीन को मेंटन करने के लिए पैसों की जरुरत पड़ती थी। वो पढ़ाई तो कर रहीं थीं।लेकिन आर्थिक तंगी के कारण शरीर के लिए जरुरी पोषण का इंतजाम नहीं कर पा रहीं थी। मुक्तेश्वरी की माने तो बेरोजगारी भत्ता से अब वो अपने लिए अच्छी डाइट का इंतजाम कर पाएंगी।

कंम्प्यूटर की पढ़ाई में नहीं होगी दिक्कत

गुढ़ियारी के रहने वाले कुणाल साहू कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कुणाल फिलहाल बीसीए की पढ़ाई कर रहे हैं। आर्थिक हालात सही नहीं होने के कारण कुणाल अपने कोर्स में इस्तेमाल होने वाली महंगी किताबें नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन अब जब उनका भत्ता स्वीकृत हो गया है तो उनकी ये परेशानी दूर हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ में आज से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू सिविल सर्विस की तैयारी करने में मिलेगी मदद-रायपुर कृष्णा नगर के दीपक निषाद ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं। दीपक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। जिसके लिए उन्हें अच्छी किताबों की जरुरत है। लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो किताबें नहीं खरीद पा रहे थे।लेकिन अब बेरोजगारी भत्ता मिलने के बाद वो ना सिर्फ अच्छी किताबें खरीदेंगे बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए दोगुनी ताकत लगाएंगे।

कैसे करें आवेदन

बेरोजगारी भत्ता लेने के लिये रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी, जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना होगा। 3 साल पुराने पंजीयन के नवीनीकरण की अंतिम तारीख बीतने के बाद भी पंजीयन वैलिड रहेगा। ऐसे आवेदकों के पास दो महीने का समय रहेगा, जिसमें वो पंजीयन का नवीनीकरण करा सकेंगे। दो माह के भीतर कभी भी आवेदक पंजीयन करवाकर योजना का लाभ ले सकता है।

आज से खुला ऑनलाइन पोर्टल - बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल 1 अप्रैल से खुल चुका है। किसी भी आवेदक को इसके लिए रोजगार दफ्तर नहीं आना होगा। आवेदन किसी भी जगह से ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। च्वाइस सेंटर्स पर भी आवेदन किया जा सकता है। इसलिए सभी आवेदकों को अपने पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज, आवास और आय प्रमाण पत्र के साथ आधार, फोटो अपलोड करना जरूरी होगा।1 अप्रैल 2021 के बाद के नए रजिस्ट्रेशन वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं।

सरकार के दावों पर सवाल

आपको बता दें कि इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं।ऐसे में बेरोजगारी भत्ता योजना लाकर कांग्रेस ने युवाओं को साधा है। इस योजना की घोषणा होने से लेकर लागू करने तक काफी तेजी दिखाई गई है। लेकिन वहीं इसके क्राइटेरिया को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। जहां कई नियम और शर्तों की वजह से कई बेरोजगार इस योजना से बाहर हो गए हैं। वहीं बेरोजगारी दर की बात करें तो रोजगार इंडेक्स के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी नहीं है। ऐसे में इतने लाख पंजीयन और उस पर योजना लाना कहीं ना कहीं सरकार के दावों पर भी सवालिया निशान लगाता है।

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की इतनी जल्दी क्यों : सिंहदेव

सरगुजा। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और आवास खाली कराने के मामले को लेकर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। जगह-जगह कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर कहा कि राहुल की सदस्यता रद्द करने की जल्दी क्यों थी? क्या भाजपा राहुल गांधी से डर रही है? सिंहदेव ने संसदीय सदस्यता खत्म करने के मामले में केंद्र सरकार को अलोकतांत्रिक करार दिया है।

24 घंटे में ही घर खाली करने का नोटिस

सिंहदेव ने कहा कि भाजपा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि भाजपा राहुल गांधी से डरती है। इसलिए उन्हें डिस्क्वॉलिफाई करने के 24 घंटे के अंदर ही घर खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया। वो तो घर खाली करते ही। लेकिन इतनी जल्दी इन्हें क्यों थी। जब कोर्ट ने अपने ही फैसले को एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है तो फिर लोकसभा सचिवालय को भी इतनी क्या जल्दी थी। अगले ही दिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री रात में स्पीकर से मुलाकात करते है। सुबह यह सूचना आती है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।

पहली बार आया ऐसा मामला

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, मेरी जानकारी में रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत यह पहला मामला है, जिसमें मानहानि के केस में सर्वाधिक दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसमें भी तेजी दिखाई गई। जबकि लाखों मामले में सुनवाई सालों नहीं होती। राहुल गांधी ने 13 फरवरी 2019 को कर्नाटक में चुनावी भाषण दिया था। इस भाषण के बाद गुजरात के सूरत में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई। फिर 7 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता ने अपनी ही शिकायत पर गुजरात हाईकोर्ट से रोक लगाने की मांग की और हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी।

लाखों मामले पेंडिंग लेकिन इसमें तत्परता

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, इन सबके बीच देशभर में 4000 किमी की भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद जब राहुल गांधी ने 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिस्तों पर सवाल उठाए। इस मामले में भाषण दिया। उसके बाद ही 16 फरवरी को शिकायतकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। फिर से निचली अदालत में 27 फरवरी से सुनवाई शुरू हो गई। ट्रायल कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम दो वर्ष की सजा सुना दी गई। उन्होंने कहा कि देश में अनेकों मानहानि के केस पेंडिंग पड़े हुए है, लेकिन इस मामले इतनी तत्परता। तत्परता भी ऐसी कि सदन में उद्बोधन देने के बाद तत्काल केस फिर से खुल गया। सुनवाई के बाद सजा भी हो गई।

कई मामले हाईकोर्ट में हुए खारिज

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। हम कानूनी प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन देश में ऐसे लाखों उदाहरण हैं, जिसमें किसी प्रकरण को लेकर उच्च अदालत में जाते है और फैसले बदल दिए जाते है।

संक्षिप्त समाचार

जांजगीर चांपा में यूथ कांग्रेस की आभार रैली

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज की कई सालों की मांग पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बजट में यह सौगात दी है। बजट में घोषणा से लोग खुश हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट की भी मंजूरी दे दी है। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में युवा कांग्रेसियों ने आभार रैली निकाली। यूथ कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज के लिए भूपेश बघेल को श्रेय देते हुए गाजे बाजे के साथ रैली निकाली। कचहरी चौक से नैला रेलवे स्टेशन तक आभार जुलूस निकाला गया। मेडिकल कॉलेज पर जमकर सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस इलाके से आते हैं और वह लगातार जांजगीर चांपा की अनदेखी का आरोप बघेल सरकार पर लगा रहे हैं। इस बार बजट को चुनावी बजट बनाने में बघेल सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी तरह को कोई टैक्स नहीं लगाया गया उसके अलावा कई तरह की सौगातें प्रदेश की जनता को सीएम भूपेश बघेल ने दी है। जांजगीर चांपा के लोग मेडिकल कॉलेज पाकर बेहद खुश हैं।

भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है- चंद्रशेखर शुक्ला

बेमेतरा। राहुल गांधी मामले को लेकर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने बेमेतरा रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस पत्रकार वार्ता में चंद्रशेखर शुक्ला, केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। शुक्ला ने भाजपा पर आरोप लगाया कि राहुल के दिये बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा राहुल गांधी अपनी बात को साफ सुथरे तरीके से कहते हैं। उनके बयान के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जो भाजपाइयों का धंधा बना हुआ है। भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। एक भ्रष्टाचारी के कारण वे संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी भाजपा लगी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंशी पटेल, बेमेतरा नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू, पीसीसी सचिव विजय बघेल समेत अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे।

बस एक क्लिक और खाते से उड़ गए दो लाख

कांकेर। पुलिस भले ही साइबर अपराध को रोकने के लिए लोगों के बीच जनजागरुकता अभियान चला रही है। लेकिन अब भी कई लोग साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं।हर रोज ठग लोगों को चूना लगाने के लिए नए तरीके अपनाते हैं। ऐसा ही एक मामला कांकेर में सामने आया।जहां पर कोरर थाना क्षेत्र में एक युवक के खाते से ठगों ने 2 लाख रुपए उड़ा लिए। कोरर थाना में स्वापन कुमार टीकादार ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। स्वापन के मुताबिक उसे एक निजी बैंक मैनेजर के नाम से फोन आया। जिसमें अकाउंट बन्द होने की जानकारी दी गई। साथ ही साथ अकाउंट को अपडेट करने के लिए कहा गया। जिसके लिए उनके बैंक खाता में लिंक मोबाइल नम्बर में एक मैसेज आया। उस मैसेज को क्लिक करने के बाद स्वापन के खाते से 2 लाख रुपए कट गए। कोरर थाने में शिकायतकर्ता की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कोरर टीआई रविशंकर साहू ने बताया कि फोन करने वाले शख्स ने खुद को बंधन बैंक का मैनेजर बताया।

राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने निकाली मशाल रैली

बेमेतरा। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द और आवास खाली कराने को लेकर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाल कर केन्द्र सरकार का विरोध किया। बेमेतरा में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में मशाल रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा के पुराना बस स्टैंड से लेकर भारत माता चौक तक रैली निकाली है। रैली में बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंसी पटेल, जिला पंचायत के सदस्य शशि प्रभा गायकवाड़ शामिल हुए। बेमेतरा जिला मुख्यालय के अलावा नवागढ़ में प्रदेश के संसदीय सचिव और नवागढ़ के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे की अगुवाई में कांग्रेसियों ने नवागढ़ बस स्टैंड से लेकर मुख्य चौक तक मशाल रैली निकाली।

एनएसयूआई ने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई का किया विरोध

रामानुजगंज। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और आवास खाली कराने को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रामानुजगंज में एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय संयोजक प्रतीक सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज में मशाल रैली निकाली। इस दौरान केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रतीक सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जो भी राहुल गांधी के साथ कर रही है, वह तानाशाही है। यह सब जनता देख रही है। भाजपा महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या पर बात नहीं करती। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया। भाजपा सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है।

विधानसभा चुनाव में ओबीसी हैं गेमचेंजर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की है नजर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश में खेमेबंदी करने में जुट गई हैं। दोनों ही पार्टियां इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को साधने में लगी हैं, जिसके लिए कई तरह की तैयारी की जा रही है। एक तरफ जहां सरकार आरक्षण और योजनाएं लाकर ओबीसी को साध रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी के बड़े पदों पर ओबीसी कैटगेरी के जनप्रतिनिधियों को बिठाकर संदेश देने की कोशिश कर रही है।राहुल पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी का रुख - राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस हंगामा खड़ा किए है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया था। इसलिए कोर्ट ने उन्हें सजा दी है। इसके लिए बीजेपी हर उस माध्यम का इस्तेमाल कर रही है, जहां जनता मौजूद रहती है।

आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का दांव : एक तरफ बीजेपी है जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद इसे ओबीसी से जुड़ा मामला बता रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो आरक्षण संशोधन विधेयक लागू नहीं होने का कारण बीजेपी को बता रही है। कांग्रेस ने 27 परसेंट ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया है, लेकिन बिल राजभवन में अटका है, जिसे लेकर कई बार कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया।

क्यों महत्वपूर्ण है पिछड़ा वर्ग: छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग की आबादी 42 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या लगभग 1 करोड़ 26 लाख है। प्रदेश के कई विधानसभा सीटों पर ओबीसी वर्ग निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में चुनाव के नजरिए से ओबीसी वर्ग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में 22 विधायक अन्य पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। मौजूदा सरकार में कांग्रेस के 18 विधायक ओबीसी वर्ग से हैं।

छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में कुल 39 सीटें एसटी-एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इन सीटों पर भी ओबीसी वर्ग का प्रभाव है। इसलिए दोनों ही पार्टियां इस बार ओबीसी वर्ग को साधकर जीत सुनिश्चित करना चाह रही हैं।लोकसभा की पांच सीटें ओबीसी की- छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में कुल 22 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं तो वहीं प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में पांच सांसद ओबीसी वर्ग से हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी से चार सांसद और कांग्रेस पार्टी से एक सांसद हैं।

क्या है राजनीति के जानकारों की राय : इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग का बड़ा हिस्सा है। विधानसभा से जब आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन गया, उस दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग का डेलिगेशन तत्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके से मिलने राजभवन गया था।

बीजापुर के गंगालूर में पुलिस नक्सली मुठभेड

बीजापुर। थाना गंगालूर क्षेत्रान्तर्गत कोरचोली, सावनार तोड़का जंगल की तरफ सीआरपीएफ के साथ पुलिस पार्टी नक्सल सर्चिंग अभियान में निकली थी। तभी सावनार तोड़का के जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर बीजीएल से हमला कर दिया।इसके बाद पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई की। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ 85 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ जारी है।

बीजापुर पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे सावनार तोड़का के जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर बीजीएल से हमला किया था। उसके बाद आत्मसुरक्षा के लिए पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की।इसके बाद कुछ देर तक दोनों ही पक्षों में मुठभेड़ चलती रही।आधे घंटे तक मुठभेड़ के बाद नक्सली मौके से भाग गए। इसके बाद जवानों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया है।

नक्सलियों ने यात्री बस में लगाई आग

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक यात्री बस में आग लगा दी। घटना जिले के मालेवाही इलाके की है। नारायणपुर से दंतेवाड़ा आ रही यात्री बस को नक्सलियों ने मालेवाही बोदली के बीच आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों के विरोध के चलते इस रोड पर आना जाना बंद था। रोड निर्माण के बाद आवाजाही शुरू की गई। जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही थी। लेकिन इसी बीच नक्सलियों ने बस में आग लगा कर दहशत फैलाने की कोशिश की। नक्सलियों ने बीते दिनों नारायणपुर में भी उत्पात मचाया था। दिनदहाड़े नक्सलियों ने रोड निर्माण में लगी तीन गाड़ियों को फूंक दिया था। खोडगांव अंजरेल माइन्स के स्कूल पारा में सीसी रोड निर्माण का काम चल रहा है।

चुनाव पास आते ही सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ी राजनेताओं की भीड़

दो माह में 24 सामाजिक कार्यक्रम, 19 में सीएम मुख्य अतिथि

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने है। राज्य में सितंबर या अक्टूबर माह में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। राजनीतिक दलों के पास समय कम और काम ज्यादा है। ऐसे में अभी से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सामाजिक संगठनों को साधना शुरू कर दिया है। इसके लिए साहू या कुर्मी जैसे बड़े जनसंख्या वाले समाज के अलावा अर्थव्यवस्था पर मजबूत पकड़ रखने वाले सिंधी समाज को भी साधने में सियासतदान जुट गए हैं। इन समाजों के कई कार्यकर्मों में ना केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा के नेता भी बढ़चढ़ कर शामिल हो रहे हैं। इसे राजनीतिक प्रेक्षक चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि पिछले एक दो माह से सामाजिक कार्य्रकमों में नेताओं का दौरा ज्यादा बढ़ गया है।

छत्तीसगढ़ में फरवरी और मार्च के बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों के 24 कार्यक्रम हुए। इसमें शपथ ग्रहण समारोह, आदर्श विवाह, युवक युवती परिचय सम्मेलन समेत कई सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं। जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि रहे। 8 ऐसे कार्यक्रम हुए, जिनमें सीएम बघेल के साथ भाजपा नेताओं ने भी मंच साझा किए हैं। चुनावी साल होने की वजह से सामाजिक संगठनों ने भी अपनी मांगें मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सियासतदान भी चुनावी मांगों पर अमल करने से पीछे नहीं हट रहे है। कहीं सामाजिक भवन की जमीन के लिए तो कहीं समाज के भवन निर्माण के लिए अनुदान राशि की घोषणा की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में आज से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरूक्या कहते हैं जानकर

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक जानकर मृगेंद्र पांडेय कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है। सियासतदानों के पास काफी कम समय बचा है। कुछ माह बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव के दौरान सभा किस तरह से होती है, सभी जानते हैं। उन सभाओं में जितनी भी भीड़ जुटती है, वह पैसों से बुलाई गई भीड़ होती है। सामाजिक कार्यकर्मों में ऐसा नहीं होता। सामाजिक कार्यक्रम में केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से समाज के लोग आते हैं। ऐसे में पॉलिटिशियन के लिए सियासी रणनीति में सामाजिक कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होता है। यही वजह है कि पिछले दो महीनों से चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के आगामी दौरे में भी बहुत से सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं।

राजधानी रायपुर में हाल ही में 23 मार्च को जयस्तंभ चौक पर झूलेलाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा के स्वागत में न केवल कांग्रेस के नेता बल्कि भाजपाइयों ने एक ही मंच से स्वागत किया। सीएम बघेल के अलावा भाजपा के विधायक और सांसद ने साथ मिलकर स्वागत किया। कर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ भाजपा सांसद सुनील सोनी भी शामिल हुए। इसके ठीक एक दिन पहले साहू समाज की बाइक रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आए। सीएम बघेल और भाजपाई 5 मार्च को गहोई वैश्य समाज के कार्यक्रम, 10 फरवरी को हरदिहा साहू समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम,15 फरवरी को सिंधी के समाज के कार्यक्रम और 10 जनवरी को व्यापारियों के कार्यक्रम में एक साथ शामिल हुए थे।इनमें सीएम हुए शामिल- फरवरी में सीएम बघेल कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 4 फरवरी को देवांगन समाज, 5 फरवरी को मनवा कुर्मी समाज। इसी दिन सदगुरु संत कबीर समागम, 8 फरवरी को रायपुर आर्च डायसिस, 10 फरवरी को हरदिहा साहू समाज, 11 फरवरी को कसेर, सोनकर, ढीमर, कहार, सतनामी व कुर्मी समाज से भेंट मुलाकात, 12 फरवरी को मनवा कुर्मी समाज, 14 फरवरी को यादव महासभा, 16 फरवरी को मराठा समाज, 19 फरवरी को मनवा कुर्मी समाज के साथ ही डडसेना कलार समाज व दिल्लीवार कुर्मी समाज के कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसी तरह मार्च महीने में भी उनका लगातार कार्य्रकम रहा। 5 मार्च को गहोई वैश्य, 12 मार्च को सिंधी समाज, झेरिया- गड़रिया समाज, 16 मार्च को शदाणी दरबार, 18 मार्च को साहू समाज, 19 मार्च को कोसरिया मरार समाज, 23 मार्च को सिंधी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की है।

छत्तीसगढ़ में 52 प्रतिशत ओबीसी हैं। इनमें सबसे ज्यादा साहू और कुर्मी समाज की संख्या है। साहू समाज के अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी कहते हैं कि प्रदेश में साहू समाज की संख्या 55 लाख से ज्यादा है। ओबीसी आबादी में 20 प्रतिशत साहू हैं। सभी क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग रह रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा से 14 और कांग्रेस से 8 लोगों को टिकट मिला था। वर्तमान में हमारे समाज के 6 विधायक हैं। कुर्मी समाज के महासचिव हिम्मत चंद्राकर कहते हैं कि हमारे समाज की जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कुर्मी समाज से आते हैं। भाजपा के कद्दावर नेता अजय चंद्राकर भी कुर्मी हैं। बहुत से विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोटरों की पकड़ है। इस बार समाज दोनों दलों से अधिक टिकट की मांग करेगा।

सीएम ने की घोषणाएं

- 10 फरवरी - हरदिहा साहू समाज को भवन के लिए जमीन
- 19 फरवरी - डडसेना कलार समाज को भवन के लिए 50 लाख व दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज को भवन के लिए 1 करोड़
- 5 मार्च - गहोई वैश्य समाज को नवा रायपुर में समाज के भवन के लिए जमीन देने की घोषणा
- 12 मार्च - मनवा कुर्मी समाज के अधिवेशन में सभी समाजों को भवन के लिए रियायती दर पर जमीन देने की घोषणा
- 13 मार्च - बहादुर कलारिन की जयंती पर सीएम ने ऐच्छिक अवकाश और महुआ बोर्ड का गठन करने के दिए निर्देश
- 16 मार्च - चेट्रीचंड्र महोत्सव पर नगर निगम के अलावा नगर पालिका क्षेत्रों में अवकाश की घोषणा।
- 18 मार्च - साहू समाज की ओट से मेडिकल कॉलेज के निर्माण में शासकीय सहायता की घोषणा

छत्तीसगढ़ में 52 प्रतिशत ओबीसी में इनकी संख्या ज्यादा

कांग्रेस ने गरीबों का निवाला छीना-डॉ रमन

विभाग ,मंत्री सबकी मिली भगत से हुआ घोटाला

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि पीडीएस का घोटाला छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि गरीब के निवाले का चावल छीनने और गरीबों के चावल में डाका डालने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। डॉ. सिंह ने कहा कि विधानसभा में इस संबंध में जब आंकड़े प्रस्तुत किए गए तो उसमें पाया गया कि खाद्य विभाग के डेटाबेस में 1.65 लाख मीट्रिक टन चावल और जिले के डेटाबेस में 96 हजार मीट्रिक टन चावल दर्ज है। प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि 68 हजार मीट्रिक टन चावल का यह अंतर क्यों आ रहा है और 600 करोड रुपए का चावल कहां गया?

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में फूड इंस्पेक्टर को डाटा दर्ज करना था और उसकी जानकारी संचालनालय को देनी थी। फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि पूरे डाटा दर्ज कर संचालनालय को जानकारी दी थी, तो इसका साफ मतलब है कि 1 साल से चल रहा यह पूरा घोटाला संचालनालय की जानकारी में था लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अब प्रदेश सरकार घपला किए गए 600 करोड़ रुपए की वसूली के लिए, सीधे-सीधे राशन दुकानों और गरीबों को इसका शिकार बना रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार और खाद्य विभाग इसके लिए दोषी है तो 2 माह का राशन देने के बाद तीसरे माह के राशन में अतिशेष आवर्तीयो का समायोजन होता है। यह प्रक्रिया भाजपा के शासनकाल से चली आ रही है, जिसे कांग्रेस के प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया है। अतिशेष के रिकॉर्ड में और जो जानकारी विभाग संचालनालय को भेजता है, उसकी अवहेलना की गई है। तो कुल मिलाकर विभाग, संचालनालय और मंत्रियों की यह मिलीभगत है, और अब छोटे-छोटे राशन दुकानदारों को इसकी वसूली केयू लिए शिकार बनाया जा रहा है। किसी राशन दुकान में चावल ज्यादा है तो यह किसकी गलती है? क्या फूड इंस्पेक्टर को मालूम नहीं है कि उसके पास भंडारण क्षमता नहीं है?

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम की कभी मिसालें दी जाती थीं, लेकिन आज इस सिस्टम को इस कदर बदनाम कर दिया है कि छत्तीसगढ़ देश में पिछड़ गया है। एक तो प्रदेश सरकार व कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 किलो मुफ्त चावल देने की जो योजना है, उसमें भी घोटाला करके प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने के बजाय प्रति परिवार 5 किलो चावल दिया गया। प्रदेश भाजपा इन सारी बातों की शिकायत केंद्र सरकार व केंद्रीय खाद्य मंत्री से करेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अभियान 'छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023' कार्य का शुभारंभ किया। इसी के तहत पूरे प्रदेश में भी 01 अप्रैल से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है।

छत्तीसगढ़ में ईडी छापे का कर्नाटक लिंक

कहते हैं कर्नाटक चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ में पिछले हफ्ते ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़े। चर्चा है कि उत्तरप्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार और अन्य कुछ राज्यों में चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ से ही कांग्रेस को ऊर्जा मिली थी। कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव में छत्तीसगढ़ से सप्लाई लाइन को काटने के लिए ईडी का इस्तेमाल हुआ। छत्तीसगढ़ में कोल और शराब कारोबार को आय का बड़ा स्रोत माना जाता है। ईडी अब तक कोल कारोबार पर ही प्रहार कर रही थी। पहली बार शराब कारोबार पर भी हथोड़ा चला दिया। आबकारी अफसर से लेकर शराब कारोबारी तक ईडी की जद में हैं। इस बार के ईडी छापे में कुछ आश्चर्यजनक नाम भी सामने आ गए। शराब कारोबार पर ईडी के नकेल से 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी असर का अंदेशा है।

ईडी के ट्रेप में उद्योगपति

छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही लगातार मलाई खाने वाले एक उद्योगपति को इस बार ईडी ने दबोच लिया। जोगी, रमन से लेकर भूपेश राज में चांदी काटने वाले ये उद्योगपति एक बीमार पवार प्लांट को खरीदने के फेर में ईडी के जाल में फंस गए। कहते हैं लोहा, खनिज और पावर के साथ दूध-दही के धंधे में डंका बजाने वाले उद्योगपति को ईडी ने ऐसा घेरा है कि उनका दलदल में फंसना तय है। खबर है कि उद्योगपति दो नंबर को एक नंबर करने के खेल में लगे थे। इस खेल के कारण ही ईडी के जाल में फंस गए। अब देखते हैं उद्योगपति ईडी के फंदे से निकल पाते हैं या फिर सलाखों के पीछे जाते हैं।

जमीनी हकीकत से रुबरू होगा संघ

रायपुर में 8 और 9 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) की दो दिवसीय मैराथन बैठक प्रस्तावित है। बताया तो यह जा रहा है कि इस बैठक में संघ की गतिविधियों पर चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी एल संतोष के अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री के मौजूद रहने की खबर से साफ़ है कि बैठक में 2023 के विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी।संघ चुनावी मुद्दों से लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों की स्थिति का आंकलन करेगा। बैठक के संयोजक दीपक विस्पुते बताए जाते हैं। वे छत्तीसगढ़ में भी संघ के प्रमुख पदाधिकारी रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि 2023 का विधानसभा चुनाव तो संघ के बलबूते पर ही भाजपा लड़ेगी , क्योंकि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है और 2018 के विधानसभा चुनाव में संघ के हाथ खींच लेने से पार्टी 15 सीटों में सिमटकर रह गई थी। खबर है कि विधानसभा चुनाव के पहले संघ जमीनी हकीकत का आंकलन कर रणनीति बना लेना चाहता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि संघ की पसंद पर ही भाजपा अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। बैठक में राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर भी बात होने की संभावना है।

कही-सुनी

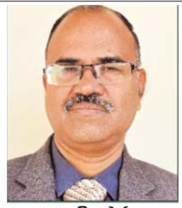

रवि भोई

मोहन मरकाम के पक्ष में सैलजा

वैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन पद पर बने हुए हैं। कहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मोहन मरकाम की जगह किसी दूसरे को चाहते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ प्रभारी सुश्री सैलजा चुनाव के छह महीने पहले अध्यक्ष को बदले जाने के पक्ष में नहीं हैं। कहते हैं कि सैलजा ने पिछले हफ्ते अपनी छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान अध्यक्ष के मुद्दे पर राज्य के कुछ नेताओं से चर्चा भी की। खबर है कि इन नेताओं ने मोहन मरकाम को फिलहाल पद पर बनाए रखने का सुझाव दिया।

नेताओं को अमित शाह की फटकार

कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते अपने बस्तर दौरे के वक्त बस्तर संभाग के कुछ भाजपा पदाधिकारियों को फटकार लगाई और गुटबाजी बंद करने की नसीहत दी। कहते हैं ये पदाधिकारी एक-दूसरे की शिकायत करने के लिए अमित शाह के पास पहुंचे थे। इस घटना के बाद लोग कयास लगाने लगे हैं कि जल्द ही अमित शाह प्रदेश स्तर के नेताओं को गुटबाजी खत्म कर एकजुट होकर चलने की नसीहत देने वाले है। खबर है कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी भाजपा नेताओं में आपसी कलह चरम पर है।

वित्त सचिव दो माह के अवकाश पर

राज्य की वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी. अस्वस्थता के कारण दो महीने के अवकाश पर चली गई हैं, उनके स्थान पर अभी लिंक अफसर अंकित आनंद वित्त विभाग का काम संभाल रहे हैं। अंकित आनंद ऊर्जा सचिव के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष भी हैं। कहा जा रहा है कि दो महीने के लिए किसी अधिकारी को वित्त सचिव नहीं बनाया जाएगा। लिंक अफसर के तौर पर अंकित आनंद ही वित्त सचिव का प्रभार देखते रहेंगे। अलरमेलमंगई के 13 मार्च से अवकाश पर जाने के बाद राज्य का बजट विधानसभा में पारित कराने और दूसरे काम अंकित आनंद के जिम्मे ही रहा। चर्चा है कि राज्य में वैसे ही अफसरों की कमी है और प्रतिनियुक्ति में गए अफसर वापस लौटने की जगह छुट्टी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी के छापे के चलते भी अफसरों के कदम ठिठकने लगे हैं।

संजय शुक्ला के बाद पीसीसीएफ कौन ?

चर्चा है कि राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय शुक्ला अप्रैल के आखिरी में या मई में रेरा के अध्यक्ष के रुप में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। संजय शुक्ला के बाद वन विभाग का मुखिया कौन होगा, अभी यह तय नहीं है। वैसे वरिष्ठता क्रम में सुधीर अग्रवाल और आशीष भट्ट का नाम है। सुधीर अग्रवाल वर्तमान में पीसीसीएफ वन्य प्राणी हैं। कुछ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अफसरों का प्रमोशन होना है। इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होनी है। डीपीसी कब होगी, निश्चित नहीं है। कहा जा रहा है डीपीसी के बाद स्थिति साफ़ होगी।

कौन होगा ईओडब्ल्यू चीफ

ईओडब्ल्यू के मुखिया के पद से डीएम अवस्थी 31 मार्च को रिटायर हो गए। सरकार ने ईओडब्ल्यू के मुखिया के पद पर अभी किसी की नियुक्ति नहीं की है। ईओडब्ल्यू के मुखिया का पद महत्वपूर्ण है। कहते हैं वर्तमान परिस्थिति में कोई अधिकारी यहां जाने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अब सरकार यहां किसी वरिष्ठ अधिकारी की पदस्थापना करती है या कनिष्ठ स्तर के अधिकारी से काम चलाती है। इस पर लोग कयास लगा रहे हैं। संभावना है कि एक-दो दिन में यहां किसी की पोस्टिंग हो जाएगी। सरकार ने संविदा नियुक्ति के लिए पुलिस मुख्यालय में ओएसडी का एक पद सृजित किया है। इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चलने की खबर है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि डीएम अवस्थी को नियुक्ति दी जा सकती है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

प्रदर्शन की नौटंकी करने की बजाय बापू और बाबा साहब से माफी मांगे कांग्रेस- चौधरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राहुल गांधी के मामले में वह महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने इन दोनों महान विभूतियों का सम्मान तो कभी किया नहीं लेकिन इनका अपमान लगातार कर रही है। कांग्रेस को बाबा साहब और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने की अपेक्षा इनसे माफी मांगनी चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया और बाबा साहब के संविधान का पालन करते हुए न्यायपालिका ने राहुल गांधी को ओबीसी समाज का अपमान करने के कारण सजा दी और कार्यपालिका ने उसका पालन किया। कांग्रेस को न्यायपालिका के फैसले पर विरोध है तो वह उच्च न्यायिक विकल्प अपना सकती है लेकिन ऐसा करने की बजाय कांग्रेस न्यायालय के फैसले पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस को बाबा साहब के संविधान पर भरोसा नहीं है। भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है।

प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कतई ईमानदार नहीं-भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कतई ईमानदार नहीं है। इस वर्ष के बजट में इसके लिए सिर्फ 250 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा गया है, वह राशि तो एक माह के भत्ता-भुगतान में ही खत्म हो जाएगी। श्री चंदेल ने कांग्रेस के जनघोषणा पत्र का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस ने 10 लाख नौजवानों को या तो रोजगार या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। कांग्रेस और उसकी राज्य सरकार साढ़े 4 साल बाद अब भी युवाओं के भारी दबाव के चलते बेरोजगारी भत्ता देने का दिखावा करने की शुरुआत कर रही है। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि इस योजना के लिए तय नियमों-शर्तों के मद्देनजर यह आईने की तरह साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश की भूपेश सरकार बेरोजगार युवकों के साथ ठीक उसी प्रकार छल कपट कर रही है जैसा उसने पूर्ण शराबबंदी, महिला स्व-सहायता समूहों की कर्ज माफी, संपत्ति कर आधा करने के वादे से मुकरकर किया है। श्री चंदेल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणापत्र में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। साढ़े चार साल का कार्यकाल बीतने तक कांग्रेस सरकार ने यह भत्ता नहीं दिया और लगातार इस तरह के किसी वादे से साफ इंकार करते हुए कांग्रेस और सरकार के मंत्री यह कहते रहे कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में हमने ऐसा कहा ही नहीं है।

भाजपा नेता की हत्या पर बोले अरुण साव कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव ने तिल्दा नेवरा क्षेत्र में घर में घुसकर भाजपा नेता की बेदम पिटाई और चाकूबाजी कर की गई हत्या पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था का रोज जिस तरह मखौल उड़ाया जा रहा है वह प्रदेश सरकार की असफलता का बड़ा प्रमाण देने के लिए पर्याप्त है। श्री साव ने कहा कि राज्य में अपराधों की बाढ़ आ गई है और दिनदहाड़े घर में घुसकर लोगों की जान लेने वाले अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश की राजधानी, उससे लगी बस्तियों-नगरों से लेकर प्रदेश के हर इलाकों में अपराधी निरंकुश हो चले हैं और प्रदेश सरकार को कानून-व्यवस्था को बेहतर बताकर अपनी झूठी वाहवाही करा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से ही फुर्सत नहीं है। यह बेहद शर्मनाक है कि अब अन्य राज्यों से अपराधियों के गैंग छत्तीसगढ़ में आकर हत्या, मारपीट, लूट, बलात्कार, अवैध वसूली, डकैती, जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। श्री साव ने कहा कि तिल्दा नेवरा के ग्राम कुंदरू निवासी भाजपा नेता जितेंद्र पाल भाजपा नशा मुक्ति अभियान के पदाधिकारी थे।

राज्य में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी लेकिन भत्ता न देकर युवाओं को छला गया: कौशिक

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ता के नाम पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस ने बेरोजगार युवकों को 'अप्रैल फूल' बनाने का काम किया है। श्री कौशिक ने कहा कि जनघोषणा पत्र में वादा करके भी 'हमने ऐसा कोई वादा अपने घोषणा पत्र में नहीं किया' कहकर बेरोजगारी भत्ता देने से मुकर जाने वाली प्रदेश सरकार साढ़े चार साल तक प्रदेश के बेरोजगार युवकों के साथ क्रूर मजाक करती रही और अब जब उस वादे पर क्रियान्वयन करने के लिए वह विवश हुई है तो पात्रता से अधिक अपात्रता के मापदंड बताकर तथा बज़ट में इस मद के लिए नाममात्र की राशि का प्रावधान करके प्रदेश के युवकों के साथ फिर छलावा करने पर आमादा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री कौशिक ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जब बेरोजगारी भत्ता के वादे का झुनझुना बजाया था, तब प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 10 लाख थी जो आज बढ़कर 18.79 लाख हो गई है। साढ़े चार साल के बाद इस वादे पर अमल के नाम पर महज़ खानीपूर्ति कर रही। प्रदेश सरकार न जाने कितने युवकों को बेरोजगारी भत्ता देगी? बेरोजगारों को छलने और और निराश करने का काम करते हुए पात्र और अपात्र की श्रेणी के जो सात मापदंड बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास पर कांग्रेस की तिकड़म समझ चुकी है जनता: धरम लाल कौशिक

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण के नाम पर जिस राजनीतिक तिकड़मबाजी का खेल प्रदेश सरकार खेल रही है, प्रदेश की जनता और प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण हितग्राही इसे भलीभाँति समझ रहे हैं। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का हक मारकर अपनी राजनीतिक चतुराई पर इतरा रही है वह कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का निकृष्ट प्रदर्शन है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री कौशिक ने कहा कि सर्वेक्षण के नाम पर सियासी तिकड़मबाजी के बजाय पहले की सर्वे सूची के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 16 लाख आवास बनाए।

इसी प्रकार शहरी और नगरीय क्षेत्र के 04 लाख आवास बनाए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास से इन हितग्राहियों को कैसे वंचित किया जाए, प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान इस पर है और इसके लिए उसने सर्वे का यह राजनीतिक पाखंड रचा है। श्री कौशिक ने कहा कि सर्वे का काम भी तब शुरू किया गया है जब कुछ ही महीनों में चुनाव आचार संहिता लगने वाली है।

छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है सांस्कृतिक एकता, इसीलिए रिश्ता है अटूट-बृजमोहन

उत्कल दिवस समारोह व जन सेवा शिविर में हुए शामिल

रायपुर। उत्कल स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर शहर में आयोजित विभिन्न समारोह में पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बैरन बाजार में ओडिशा आंदोलन के जनक साहित्यकार मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। पश्चात शांति नगर में ऑल छत्तीसगढ़ उत्कल कल्याण संगठन आयोजित जनसेवा शिविर में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित उत्कल समाज के लोगों को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि उड़ीसा और प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ का अटूट संबंध रहा है। उडिया और छत्तीसगढिया में भी सांस्कृतिक एकता है। यही वजह है कि रायपुर सहित राज्य के विभिन्न शहरों में उडिया समाज के लाखों लोग रहते हैं और यहां के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्कल कल्याण संगठन द्वारा आयोजित आधार कार्ड, मजदूर कार्ड, पैन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड,राशन कार्ड शिविर पर कहा कि संगठन द्वारा यह नेक कार्य निश्चित रूप से लोगों के लिए राहत देने वाला होगा। इसी तरह लोग या सामाजिक संगठन अपनी सामाजिक जवाबदेही को समझकर लोगों की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर समाज की स्थापना होगी। इस अवसर पर गोपाल बाघ,सत्यानंद तांडी,ऑल छत्तीसगढ़ उत्कल कल्याण संगठन के वासुदेव तांडी,राजेश तांडी,विजय छुरा,संतोष सोनी,महेश बघेल,राहुल बघेल आदि उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का राजनैतिक प्रस्ताव पारति

रायपुर। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ चौलेश्वर चंद्राकर के नेतृत्व में आयोजित पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक मेंराजनीतिक प्रस्ताव पारित राजीव भवन में आहूत पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक में आज पिछड़े वर्ग कांग्रेस के नेता प्रदेशभर से जुटे हुए थे। जहां पिछड़ा वर्ग समुदाय के कई विधायकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में पिछड़े वर्ग को लेकर किसी तरह की गलतफहमी में बीजेपी ना रहे। आज बैठक में पहली बार यह देखा गया कि 10 बिंदुओं में एक राजनीतिक प्रस्ताव लाकर उसे सर्वसम्मति से पास किया गया। जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए जा रहे कार्यों को शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंचाने और पंचायत स्तर में भी इस वर्ग का प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात कही गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए पिछले साडे 4 सालों में छत्तीसगढ़ के लिए लाई गई विभिन्न योजनाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाने का कार्य पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के पदाधिकारी करेंगे। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ने तय किया है कि इस वर्ग के पदाधिकारी अब पंचायत स्तर में भी अंतिम व्यक्ति तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एवं सरकार की योजनाओं को पहुंचाने प्रतिनिधि नियुक्त कर उनके माध्यम से सक्रिय होगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी को टारगेट कर सताने का प्रयास किया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति के उद्देश्य से भाजपा पिछड़े वर्ग को इसमें समाहित कर रही है इस बात को विस्तार पूर्वक शहर से लेकर गांव के लोगों तक पहुंचाने जन अभियान चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने पिछड़े वर्ग के उत्थान को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस वर्ग की पहचान व उनकी महत्ता को प्रतिपादित किया है। उसे प्रदेश भर में प्रचारित करने का कार्य पिछड़ा वर्ग कांग्रेस करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यप्रणाली पिछड़े वर्ग को को उपकृत करने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर में हम पूरी तरह सफल तो हैं परंतु लोकसभा के चुनावों में इसका लाभ क्यों नहीं मिल पाता पर भी विस्तृत रिसर्च किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस इस बात पर भी गहन विचार विमर्श के साथ कार्य करेगी की पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ समुचित मिल रहा है या नहीं और भविष्य में किस तरह की अन्य योजनाओं पर भी कार्य होना चाहिए पर चर्चा करेगी। कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी द्वारा देश हित में उठाए जा रहे मुद्दों के चलते घबराहट में भाजपा किस तरह के हथकंडे अपनाकर अपना राजनीतिक हित साधने के साथ लोगों को गुमराह कर रही है पर भी पिछड़ा वर्ग कार्य करेगी।

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस उपरोक्त कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने शहर से लेकर पंचायत स्तर पर जगह जगह बैठकें आयोजित कर ब्लॉक स्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। प्रदेश में भूपेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में एवं अन्य सरकारी योजनाओं में लाभ देने जनसंख्या के आधार पर जिस तरह से आरक्षण का निर्धारण किया है। जिसका लाभ इस वर्ग को न मिले को लेकर भाजपा प्रदेश में किस तरह का षड्यंत्र कर रही है को भी जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस वर्ग के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करने गांव गांव तक प्रचार प्रसार करेगी। ताकि उनके चेहरे के सामने किसी अन्य पार्टी का नेता यह साबित करने सफल ना हो सके की उनके पास भी इस वर्ग के लिए कोई चेहरा है। आज की बैठक में उपरोक्त 10 मुद्दों को लेकर समस्त वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं व पदाधिकारियों की उपस्थिति में राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया।

ओबीसी कांग्रेस के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। टर्निंग पॉइंट शंकर नगर चौक में झंडा लेकर नारे बाजी कर मोदी सरकार के विरूद्ध ओबीसी के साथियों ने विरोध किया है। साथ ही चरणबद्ध तरीका से ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन ओबीसी कांग्रेस के द्वारा किया जायेगा। विधायक द्वय धनेन्द्र साहू, संगीता सिन्हा, श्रीमती ममता चंद्राकर, पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू, पूर्व सांसद छाया वर्मा, सीमा वर्मा, द्वारिका साहू ने भी संबोधित किया। प्रभारी महामंत्री श्री नचिकेता जायसवाल ने आभार व्यक्त किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.